Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-13-14 01-15—16-31 जुलाई, 2024 (संयुक्तांक) ₹20

'21वीं सदी भारत की है'

"तीसरे कार्यकाल में हम तीन गुनी गति से काम करेंगे, तीन गुनी ऊर्जा लगाएंगे और तीन गुना परिणाम देंगे"

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 06 जुलाई, 2024 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

तिरुवनंतपुरम (केरल) में 09 जुलाई, 2024 को प्रदेश भाजपा विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते केरल भाजपा के नेतागण

मैजेस्टिक ग्रैंड (जम्मू एवं कश्मीर) में 06 जुलाई, 2024 को प्रदेश भाजपा विस्तारित कार्यकारिणी बैठक के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 25 जून, 2024 को आयोजित 'लोकतंत्र का काला दिवस' कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत कुमार गौतम, श्री तरुण चुघ एवं श्री विनोद तावड़े

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में 22 जून, 2024 को लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत एवं प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

पंचकुला (हरियाणा) में 29 जून, 2024 को प्रदेश भाजपा विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण

06 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि 2024 का चुनाव नीति, इच्छा, समर्पण और निर्णयों में विश्वास का चुनाव है...

11 'राष्ट्र प्रथम' ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है: नरेन्द्र मोदी

दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार चुनने के लिए...

15 विकसित भारत 140 करोड़ नागरिकों का मिशन है: नरेन्द्र मोदी

देश की लोकतांत्रिक यात्रा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 60 वर्षों के बाद भारत के मतदाताओं ने...

20 ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 15 प्रतिशत है: जगत प्रकाश नड्डा

मैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर धन्यवाद देने के लिए और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए इस...

38 22वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 जुलाई, 2024 को 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए...

वैचारिकी

भारतीय जनसंघ ही क्यों? / **डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी** 28

लेख

सुशासन के प्रतीकः छत्रपति शिवाजी महाराज / **शिवप्रकाश** 30

गुरु पूर्णिमा का है ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्त्व / **तरुण चुघ** 31

मन की बात

मैंने भी एक पेड़ अपनी 'मां' के नाम लगाया है: नरेन्द्र मोदी 41

अन्य

कांग्रेस ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया : जगत प्रकाश नड्डा 22

कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया: प्रधानमंत्री 23

केरल की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी है : जगत प्रकाश नड्डा 24

भाजपा हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक, पंचकुला 26

नए प्रदेश प्रभारी एवं सह-प्रभारी नियुक्त 27

अपने तीसरे कार्यकाल में हम तीन गुना अधिक श्रम करेंगे और तीन गुना अधिक परिणाम अर्जित करेंगे: नरेन्द्र मोदी 33

ओम बिरला 18वीं लोकसभा के चुने गए अध्यक्ष 34

3 नए आपराधिक कानून 01 जुलाई से हुए लागू 35

योग केवल एक विधा ही नहीं अपितु एक विज्ञान भी है: नरेन्द्र मोदी 37

539 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ 40

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

संदेशखाली जैसी शर्मनाक घटना पर कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन के नेताओं को कोई पीड़ा नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर विपक्ष का यह सलेक्टिव रवैया बहुत चिंताजनक है।

(04 जुलाई, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

जो 'चांदी का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेते हैं,' उन्हें गरीबी का कोई अंदाजा नहीं होता। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों ने गांव, गरीब और आम आदमी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है, गरिमा व सम्मान का जीवन प्रदान किया है।

(02 जुलाई, 2024)

अमित शाह

जब 2029 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाएगा, तब देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी, जहां पैक्स नहीं होगा।

(06 जुलाई, 2024)

राजनाथ सिंह

मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वो संसद को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से, 158 संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया, उनके सुझाव लिए गए, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है।

(01 जुलाई, 2024)

बी.एल. संतोष

जो लोग कू (Koo) का मजाक उड़ा रहे हैं और इसके बंद होने का जश्न मना रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि आप हमारे युवा उद्यमियों की 'कभी न हार मानने वाली' प्रवृत्ति को मार रहे हैं। आप युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आप भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको!

(04 जुलाई, 2024)

निर्मला सीतारमण

रूसी संघ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित किया गया। यह भारत एवं वैश्विक पटल पर उसके कद को चिह्नित करता है। प्रधानमंत्री मोदीजी ने यह पुरस्कार भारत के लोगों को समर्पित किया।

(09 जुलाई, 2024)

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर

संपादकीय

आज जब पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की तीसरी पारी के शुभारंभ का उत्सव मना रहा है, जन-जन के मन में 'विकसित भारत' का संकल्प और भी अधिक दृढ़ हुआ है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब तीसरी बार लगातार देश ने मोदी सरकार को उसके अद्वितीय कार्यों एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। लोगों ने पुनः श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया तथा उनके 'विकसित भारत' के स्वप्न को भारी समर्थन दिया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कोने-कोने में अपने अथक अभियान से 'विकसित भारत' के संदेश को गुंजायमान किया। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र पर उनकी गहरी प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, किसान, महिला एवं युवा ने उनके नेतृत्व पर अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है तथा देश के लिए उनके सपनों पर भारी विश्वास व्यक्त किया है। अमृतकाल में 18वीं लोकसभा का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए विश्वास से पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब देश नई ऊचाइयों को छूने के लिए तत्पर है।

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत की राष्ट्रपति माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए देश की सेवा करेंगे। एक ओर जहां राष्ट्रपति जी ने 2024 के लोकसभा चुनावों की व्यापकता को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में भारी मतदान के साथ-साथ महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की भी प्रशंसा की। देश द्वारा स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार लगातार स्थिर सरकार के चुनाव से पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। ऐसा छह दशकों के पश्चात् हुआ है, इसलिए लोगों का यह जनादेश और भी अधिक अभिनंदनीय है। 'रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म' का मंत्र, जिससे भारत ने व्यापक परिवर्तन के साथ चमत्कृत करने वाली उपलब्धियां प्राप्त कीं, उस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आज देश विश्व की सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले वर्षों में भारत ने 8 प्रतिशत तक का विकास दर प्राप्त किया, विश्व अर्थव्यवस्था में 15 प्रतिशत योगदान दिया तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह सब गरीब, किसान, अनु. जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। अभिनव योजनाओं से आज देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अब अन्य उपेक्षित क्षेत्रों का सशक्तीकरण किया गया है।

> **आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपनी तीसरी पारी में तीन गुना अधिक मेहनत कर रहे हैं, देश का विकास नई ऊर्जा एवं द्रुत गति से नए रिकॉर्ड बनाएगा**

आज जब पूरा देश नवनिर्वाचित सांसदों से जनहित में सकारात्मक राजनीति के सिद्धांतों के अनुरूप संसद में स्वस्थ बहस की अपेक्षा कर रहा है, इंडी-गठबंधन द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग तथा देश एवं समाज को जाति, मजहब एवं क्षेत्र के आधार पर विभाजित करने का दुर्भाग्यपूर्ण कुचक्र रचा जा रहा है। यह अत्यंत दुःखद है कि नेता प्रतिपक्ष जिन्हें संसदीय मूल्यों की उच्च परंपरा का सम्मान करना चाहिए, उन्होंने अपने पहले भाषण में ही देश के बहुसंख्यक समाज को हिंसक एवं नफरत फैलाने वाला बताने का निंदनीय कार्य किया। देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर के दौरान विपक्ष द्वारा हंगामे से बाधा डालने का असहिष्णु रवैया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय एवं भर्त्सना करने योग्य है। विपक्ष को इस तरह के लोकतंत्र-विरोधी आचरण से बचना चाहिए, इसे लोकतंत्र में कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आपातकाल पर सदन में प्रस्ताव लाकर एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। इससे पूरे देश को भारतीय राजनैतिक इतिहास के इस काले अध्याय की याद दिलाया गया, जिससे हम अतीत में हुई गलतियों से सबक ले देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति सजग रहें। अब जब भारत 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए आगे बढ़ चुका है, अतीत के सबक तथा इतिहास की उपलब्धियों के प्रति गौरव देश की इस यात्रा को दिशा दिखाएंगे। आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपनी तीसरी पारी में तीन गुना अधिक मेहनत कर रहे हैं, देश का विकास नई ऊर्जा एवं द्रुत गति से नए रिकॉर्ड बनाएगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

‘21वीं सदी भारत की है’

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 27 जून, 2024 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए 18वीं लोकसभा में चुनकर आए सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मतदाताओं द्वारा सौंपे गए विशेषाधिकार और जिम्मेदारी पर जोर देते हुए उन्होंने ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ राष्ट्र की सेवा के प्रति उनके समर्पण पर विश्वास व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के व्यापक परिदृश्य पर प्रकाश डाला और लोकसभा में हुए 64 करोड़ रिकॉर्ड मतदान का उल्लेख किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर की भागीदारी की सराहना की। श्रीमती मुर्मु ने इस बात का भी उल्लेख किया कि देश की महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की मुख्य बातें निम्न हैं:

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि 2024 का चुनाव नीति, इच्छा, समर्पण और निर्णयों में विश्वास का चुनाव है:

- एक मजबूत और निर्णायक सरकार पर विश्वास
- सुशासन, स्थिरता और निरंतरता पर विश्वास
- ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर विश्वास
- सुरक्षा और समृद्धि पर विश्वास
- सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास
- भारत के ‘विकसित भारत’ बनने के संकल्प पर विश्वास

- श्रीमती मुर्मु ने भारत की स्थिर सरकार के वैश्विक महत्व को रेखांकित किया, जिसे लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए स्पष्ट बहुमत से चुना गया है। उन्होंने बताया कि यह 6

दशकों के बाद हुआ है। श्रीमती मुर्मु ने सरकार के 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के संकल्प पर जोर दिया और भारत की आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिसमें इसे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बदलने का श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्ष 2021 से 2024 तक भारत ने औसतन 8% वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति की है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत अकेले वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 15% का योगदान दे रहा है और सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

- श्रीमती मुर्मु ने यह भी बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों— विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को समान महत्त्व दे रही है। पी.एल.आई. योजनाओं और 'कारोबार में सुगमता' (Ease of Doing Business) के लिए किए गए उपायों ने बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि में योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3,20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित

- किसानों को उनकी छोटी-मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3,20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। अपने नए कार्यकाल के प्रारंभिक दिनों में ही सरकार ने किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में रिकॉर्ड वृद्धि भी की है। इसके साथ ही, सरकार एक बड़े पैमाने पर किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और PACS जैसी सहकारी संगठनों का नेटवर्क बना रही है।
- श्रीमती मुर्मु ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य हरित युग का होगा और सरकार हरित उद्योगों में अग्रणी भूमिका निभा रही है, जिससे हरित रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है।
- माननीया राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा किए गए कई महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों और पहलों को उजागर किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है, जो अप्रैल, 2014 में 209 एयरलाइन रूट्स से बढ़कर अप्रैल, 2024 तक 605 रूट्स तक पहुंच गया है। इस विस्तार से देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों को विशेष रूप से लाभ हुआ है। पिछले 10 वर्षों में मेट्रो सेवा भी 21 शहरों तक पहुंच चुकी है।

भारत अकेले वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 15% का योगदान दे रहा है और सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कृतसंकल्प है

संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने प्रगति और सुशासन की रुपरेखा प्रस्तुत की: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून को कहा कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण व्यापक था और इसने प्रगति एवं सुशासन की रुपरेखा प्रस्तुत की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के मूल पाठ का एक लिंक भी साझा किया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति जी का संबोधन व्यापक था और इसने प्रगति एवं सुशासन की रुपरेखा प्रस्तुत की। इसमें भारत द्वारा की जा रही प्रगति और आगे की संभावनाओं को भी शामिल किया गया। उनके अभिभाषण में कुछ प्रमुख चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया, जिनसे हमें अपने नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक रूप से निपटना होगा।"

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सरकार ने पिछले दशक में 3,80,000 किलोमीटर से अधिक गांवों की सड़कों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, जिससे ग्रामीण संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है और निर्माण की गति दोगुनी से अधिक हो गई है।
- एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहल के अंतर्गत असम में 27,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य उत्तर-पूर्व को देश में निर्मित सेमीकंडक्टर्स के हब के रूप में स्थापित करना है, जो 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप है।

महिलानीत विकास

- माननीया राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार के महिलानीत विकास और सशक्तीकरण के प्रति स्थिर प्रतिबद्धता को उजागर किया, जो राष्ट्र की प्रगति में एक नये युग की निशानी है। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधान से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर महिलाओं को सशक्त किया गया है।
- एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है 3 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना, स्व-सहायता समूहों को अधिक वित्तीय सहायता के साथ समर्थन देकर।

इस पहल का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक कौशल और अवसरों में सुधार करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं के स्थान और सम्मान को भी बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

- 'नमो ड्रोन' दीदी योजना इस उद्देश्य में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसमें कई स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन दिया जा रहा है और उन्हें ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस नवाचारी पहल से न केवल उनकी क्षमताओं में सुधार हो रहा है, बल्कि उन्हें तकनीकी प्रगति में शामिल किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ाया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास घरों में बहुमति महिला लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कृषि सखी पहल शुरू की है। अब तक स्व-सहायता समूहों से 30 हजार महिलाओं को कृषि सखी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण कृषि कौशल और संसाधनों से सशक्त किया गया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

- श्रीमती मुर्मु ने समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए कई परिवर्तनकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इनमें से एक प्रमुख योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसका लक्ष्य बिजली के बिलों को शून्य करना और शेष बिजली को बेचकर आय प्राप्त करना है। इस पहल में घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाना शामिल है, जिससे प्रत्येक परिवार को सरकार से 78,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी।
- राष्ट्रपति जी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की योजनाओं को सही दृष्टिकोण से लागू करने के कारण 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर लाया गया है। कोरोना महामारी के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' शुरू की।

पीएम जनमन

- श्रीमती मुर्मु ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के साथ 'पीएम जनमन' योजना सबसे वंचित जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। यह उनकी उन्नति और सशक्तीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
- राष्ट्रपति जी ने बताया कि वंचित समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पीएम-सूरज पोर्टल लॉन्च किया है, जो सॉफ्ट लोन तक पहुंच को आसान बनाता है। इस पहल का उद्देश्य कमजोर समुदायों के बीच रोजगार के अवसर

पैदा करना और आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार करना है।

- समावेशिता की दिशा में एक सराहनीय प्रयास करते हुए सरकार दिव्यांगों के लिए सस्ती स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस पहल का उद्देश्य देशभर में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच और समर्थन को बढ़ाना है।
- श्रीमती मुर्मु ने डिजिटल इंडिया और डाकघर नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा की कवरेज को व्यापक बनाने के सरकार के प्रयासों की भी सराहना की, जिससे नागरिकों के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सरकार देश में शिक्षा और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना भी आगे बढ़ा रही है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 7 नए IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 नए AIIMS, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, छात्र अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकते हैं और अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने देश के युवाओं की क्षमता को बढ़ाने में मदद की है।

पीएम स्वनिधि का दायरा बढ़ा

- श्रीमती मुर्मु ने बताया कि पीएम स्वनिधि का दायरा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा, जो कि स्ट्रीट वेंडरों को सहायता के अलावा इन क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को और मजबूती प्रदान करेगा।
- सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि सरकार 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत 55 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को कवर किया जाएगा। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों की स्थापना भी प्रगति पर है।
- पब्लिक सेक्टर बैंकों पर बात करते हुए श्रीमती मुर्मु ने कहा कि पी.एस.बी ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। इस वित्तीय स्थिरता ने उन्हें अधिक ऋण देने में सक्षम बनाया है, जिससे राष्ट्र के आर्थिक विकास को समर्थन मिला है। इसके अलावा, जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने का माध्यम बन गया है और व्यापार को पहले से आसान बना रहा है। पहली बार, अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिससे राज्यों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है।
- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुधार को उजागर किया, जिसमें 40 से अधिक ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को 7 रक्षा क्षेत्र उद्यमों में समेकित किया गया है। ये सुधार उनकी क्षमता और कुशलता में वृद्धि करने में बहुत मदद करते हैं, जिससे भारत को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की रक्षा उपकरणों के निर्माण की क्षमता मिली है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सशस्त्र बलों की जरूरतों को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप 4 दशकों के बाद 'वन रैंक वन पेंशन' लागू की गई है। इसके अंतर्गत, अब तक 1,20,000 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
- इसके अतिरिक्त, अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहल देश की युवा शक्ति के कौशल और उद्यमी क्षमताओं को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है।

> **सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शरणार्थियों को नागरिकता देने की भी शुरुआत की है, जिससे विभाजन से प्रभावित कई परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो रहा है**

विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में

- श्रीमती मुर्मु ने रेखांकित किया कि भारत अब वैश्विक रूप से तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने 'मेरा युवा भारत (MY भारत)' अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक युवा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करना और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति जी ने अपनी सरकार के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही युवा भारतीय खिलाड़ियों द्वारा वैश्विक मंचों पर जीते गए रिकॉर्ड संख्या मेडल्स का भी जिक्र किया। इसके अतिरिक्त, श्रीमती मुर्मु ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की तैयारी कर रहा है।
- सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत शरणार्थियों को नागरिकता देने की भी शुरुआत की है, जिससे विभाजन से प्रभावित कई परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो रहा है। राष्ट्रपति जी ने इन परिवारों के बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई।

भव्य नालंदा विश्वविद्यालय

- श्रीमती मुर्मु ने यह भी कहा कि भविष्य का निर्माण करते

हुए सरकार भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को पुनः स्थापित कर रही है। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य परिसर के रूप में इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण था। राष्ट्रपति जी को विश्वास है कि नया नालंदा विश्वविद्यालय भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। इसके अलावा, 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना से काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम जैसे त्योहारों को मनाने की परंपरा भी सरकार ने शुरू की है।

भारत: लोकतंत्र की जननी

- माननीया राष्ट्रपति जी ने विश्व स्तर पर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की प्रतिष्ठित स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लोग लगातार लोकतंत्र में विश्वास प्रदर्शित करते हैं और चुनावी संस्थाओं में उनका अटूट विश्वास है। उन्होंने भारत के मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए इस विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
- प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र प्रगति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने इसके दुरुपयोग की संभावना को स्वीकार किया तथा ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए रूपरेखाएं स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया। भारत ने वैश्विक मंचों पर इन चिंताओं को सक्रिय रूप से व्यक्त किया है तथा इन चुनौतियों का मुकाबला करने और नए समाधान खोजने के लिए सामूहिक प्रयासों की सराहना की है।

> **25 जून, 1975 को लगाया गया आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरा देश आक्रोशित था, लेकिन देश ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर विजयी हुआ, क्योंकि गणतंत्र की परंपराएं भारत के मूल में हैं**

विश्व-बंधु के रूप में भारत

- श्रीमती मुर्मु ने विश्व-बंधु के रूप में भारत की उभरती भूमिका को रेखांकित किया और इसका श्रेय मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दिया। भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान कई मुद्दों पर दुनिया को एकजुट किया। इसी दौरान अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।
- हमारी सरकार मोटे अनाज 'श्री अन्न' को सुपर फूड के रूप में दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का अभियान भी चला रही है। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया।
- भारत ने संकट के समय सक्रिय प्रतिक्रिया देने वाले राष्ट्र रूप में अंतरराष्ट्रीय विश्वास हासिल किया है और ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। चाहे COVID-19 महामारी का प्रबंधन हो, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना हो या संघर्षों के दौरान शांति के लिए आवाज उठानी हो; भारत ने मानवता की सुरक्षा और वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों में लगातार नेतृत्व किया है।
- राष्ट्रपति जी ने यह भी याद दिलाया कि 25 जून, 1975 को लगाया गया आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरा देश आक्रोशित था, लेकिन देश ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर विजयी हुआ, क्योंकि गणतंत्र की परंपराएं भारत के मूल में हैं।

संविधान के प्रति गहन सम्मान

- माननीया राष्ट्रपति जी ने भारत के संविधान के प्रति अपनी सरकार के गहन सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल शासन संबंधी दस्तावेज नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला है। जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की पहल की, जिसका उद्देश्य संविधान को जन चेतना में गहराई से समाहित करना है। इसके अतिरिक्त, श्रीमती मुर्मु ने जम्मू और कश्मीर में संविधान के पूर्ण एकीकरण का उल्लेख किया, जो पहले अनुच्छेद 370 के कारण अलग-अलग परिस्थितियों में शासित था।
- पिछले दशक के परिवर्तनकारी सुधार और नए आत्मविश्वास पर विचार करते हुए राष्ट्रपति जी ने एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक नई गति की बात की। उन्होंने दोहराया कि यह आकांक्षा हर नागरिक की है और इस मार्ग पर आने वाली बाधाओं को दूर करने में सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।
- भारत के प्राचीन ज्ञान का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा, 'समानो मंत्रः समितिः समानी' और सांसदों से 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के साझा विचार और लक्ष्य के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।
- इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की है, श्रीमती मुर्मु ने कहा कि इसका प्रभाव आने वाली सदियों तक रहेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का आग्रह करते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक 'विकसित राष्ट्र' के रूप में भारत के भाग्य को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। ■

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का उत्तर

'राष्ट्र प्रथम' ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दिया। सदन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त किया और अभिभाषण का केन्द्र बिन्दु रहे 'विकसित भारत' के विचार पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद भी किया। श्री मोदी ने विशेष रूप से पहली बार संसद में आए उन सांसदों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सदन के नियमों का सम्मान करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार किसी भी अनुभवी सांसद से कम नहीं था और उनके विचारों ने इस बहस की गरिमा को और समृद्ध किया है:

दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार चुनने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने लगातार तीसरी बार वर्तमान सरकार को चुनने के लिए भारत के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे लोकतांत्रिक दुनिया में गौरव का क्षण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार के प्रयास मतदाताओं के लिए निर्णायक रहे थे और उन्होंने 'जन सेवा ही प्रभु सेवा' यानी मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, की मान्यता के साथ नागरिकों की सेवा करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया किया कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतने कम समय में 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

2014 के बाद भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस

2014 के बाद भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के रुख को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के मतदाताओं ने उन्हें फिर से सत्ता में पहुंचाया है। "आज पूरी दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हर भारतीय अब गौरवान्वित महसूस करता है।" श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की हर नीति, निर्णय और काम में भारत को प्राथमिकता दी जाती है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति दुनिया का नजरिया बदल गया है और यह हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। श्री मोदी ने 'राष्ट्र प्रथम' के एकमात्र उद्देश्य पर जोर दिया जिसकी झलक सरकार की नीतियों और निर्णयों में नजर आती है। इसी विश्वास के साथ श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पूरे देश में सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र और 'सर्व धर्म समभाव' के सिद्धांतों के साथ लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ ही है सभी धर्म समान हैं।

राजग सरकार ने लोगों की संतुष्टि और पुष्टि के साथ काम किया

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण के शासन मॉडल को लंबे समय से देखा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में पहली बार उनकी सरकार ने लोगों की संतुष्टि और पुष्टि के साथ धर्मनिरपेक्षता की दिशा में काम किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए संतुष्टि का मतलब सरकार की विभिन्न नीतियों में परिपूर्णता प्राप्त करना और भारत के अंतिम व्यक्ति तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उनके संकल्प को पूरा करना है। श्री मोदी ने कहा कि उनके लिए संतृप्ति यानी परिपूर्णता का यह दर्शन,

सही मायने में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का मतलब है और इसे भारत के लोगों ने लगातार तीसरे कार्यकाल के रूप में अनुमोदित किया है।

लोगों ने हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव ने एक बार फिर भारत के लोगों की परिपक्वता और आदर्शवाद को साबित कर दिया है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "लोगों ने हमारी नीतियों, इरादों और प्रतिबद्धता पर भरोसा दिखाया है।" उन्होंने कहा कि लोगों ने इस चुनाव में विकसित भारत के संकल्प का समर्थन किया है।

विकसित राष्ट्र के महत्त्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब देश आगे बढ़ता है तो हर नागरिक के सपने पूरे होते हैं और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की नींव भी रखी जाती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लोग विकसित भारत के लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसके लिए पिछली पीढ़ियां हमेशा तरसती रही थीं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण से भारत के गांवों और शहरों के रहन सहन और जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा, साथ ही लोगों में गर्व की भावना पैदा होगी और उनके लिए असंख्य अवसर पैदा होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया, "भारत के शहर दुनिया के अन्य विकसित शहरों के साथ समान रूप से भागीदारी करेंगे।"

> जब देश आगे बढ़ता है तो हर नागरिक के सपने पूरे होते हैं और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की नींव भी रखी जाती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लोग विकसित भारत के लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं

'विकसित भारत' का तात्पर्य प्रत्येक नागरिक के लिए कई और समान अवसरों की उपलब्धता

श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का तात्पर्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कई और समान अवसरों की उपलब्धता से है। इससे कौशल, संसाधनों और क्षमता के आधार पर सभी के लिए विकास सुनिश्चित होता है।

श्री मोदी ने देश के नागरिकों को भरोसा दिलाया कि सरकार विकसित भारत के उद्देश्य को पूरी ईमानदारी और ईमानदारी के साथ साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "हर पल और हमारे शरीर की हर कोशिका विकसित भारत 2024 बनाने के विचार के लिए सातों दिन के 24 घंटे समर्पित है।"

प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले के दौर को याद किया जब पूरा देश निराशा की स्थिति में था। नागरिकों के बीच विश्वास की कमी को उस दौरान देश के लिए सबसे बड़ी क्षति बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे निराशा के बादल छा गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि यह घोटालों और पॉलिसी पैरालिसिस से भरा युग था जिसने देश को पांच कमजोर (फ्रैजाइल 5) अर्थव्यवस्थाओं की सूची में धकेल दिया था। उन्होंने कहा कि आम नागरिक सारी उम्मीदें खो चुके थे। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी आम बात थी, चाहे वह घर के लिए हो, गैस कनेक्शन के लिए हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज प्राप्त करने के लिए हो।

श्री मोदी ने कहा कि देश के नागरिक 2014 से पहले सरकार की खराब स्थिति के लिए अपने भाग्य को दोष देते हुए दैनिक जीवन को जीने के लिए मजबूर थे। उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें चुना, बदलाव के दौर की शुरुआत की।"

सरकार की उपलब्धियां

श्री मोदी ने उन लोगों को बदलने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जो कभी सोचते थे कि कुछ भी संभव नहीं है। अब उन्हें विश्वास हो रहा है कि सब कुछ संभव है। सरकार की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए प्रधानमंत्री ने एक सफल 5 जी रोलआउट, उच्चतम कोयला उत्पादन, देश की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी नीतियों, आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का उल्लेख किया। उन्होंने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में रिकॉर्ड मतदान का उल्लेख करते हुए कहा, "जैसे-जैसे अनुच्छेद 370 की दीवारें ढहाई जा रही हैं, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।"

श्री मोदी ने कहा, "140 करोड़ नागरिकों का विश्वास, उम्मीदें और भरोसा विकास की प्रेरक शक्ति बनते हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विश्वास दृढ़ संकल्प द्वारा कार्यसिद्धि का प्रतीक है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिक आज भी उतने ही उत्साहित और आश्वस्त हैं, जितने वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थे। पिछले 10 वर्षों में देश की प्रगति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "आज भारत को खुद से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है। हमें अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने होंगे और देश को अगले स्तर पर ले जाना होगा।" श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने विकास का जो रास्ता अपनाया है, वह अब एक बेंचमार्क बन गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश तेज गति से प्रगति करेगा और कहा, "हम हर क्षेत्र को अगले स्तर पर ले जाएंगे।"

भारत जल्द ही बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

श्री मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के अब दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल निर्माताओं और निर्यातकों में से एक

बनने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने भरोसा व्यक्त किया कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी इसी तरह की ऊंचाइयों को छुएगा।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि जहां देश नई उपलब्धियां हासिल करेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा, वहीं सरकार आम नागरिकों की सेवा में समर्पित रहेगी। श्री मोदी ने गरीबों को दिए गए 4 करोड़ पक्के घरों का जिक्र किया और बताया कि आने वाले समय में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्थान का ज़िक्र करते हुए श्री मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की सरकार की कार्ययोजना के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज़ी और प्रयास से काम करने और तीन गुना परिणाम देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

लोगों ने स्थिरता और निरंतरता को चुना

श्री मोदी ने कहा कि 60 साल बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आना सरकार के प्रयासों और नागरिकों के बीच उसके द्वारा कायम किए गए विश्वास का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा, "ऐसी उपलब्धियां तुच्छ राजनीति से नहीं बल्कि नागरिकों के आशीर्वाद से हासिल होती हैं।" उन्होंने कहा कि लोगों ने स्थिरता और निरंतरता को चुना है।

प्रधानमंत्री ने चार राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में मिले जनादेश की भी सराहना की और लोकसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिली भारी जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने देश भर के कई राज्यों में बढ़ते वोट शेयर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "जनता जनार्दन हमारे साथ है।"

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर विचार करते हुए श्री मोदी ने विपक्ष से विनम्रता के साथ जनादेश को स्वीकार करने और लोगों के संदेश को समझने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और वे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। भारत को सामूहिक रूप से विकास की एक नई यात्रा शुरू करने की जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के नागरिकों से अराजकता, अव्यवस्था और विभाजनकारी राजनीति का रास्ता चुनने वालों के खिलाफ सतर्क रहने को कहा। उन्होंने देश को आर्थिक अराजकता की ओर धकेलने वाली अनुपयुक्त हो चुकीं आर्थिक नीतियों और देश में गलत सूचनाओं के प्रसार के खिलाफ भी चेतावनी दी। श्री मोदी ने अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष से सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने का भी आग्रह किया और अध्यक्ष को सुधारात्मक उपाय करने का सुझाव दिया ताकि सदन की पवित्रता बरकरार रहे।

आपातकाल में व्यापक क्रूरता हुई

आपातकाल के दौर के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पर शासन करने वालों ने देश में तानाशाही का माहौल बनाया था, जिससे नागरिकों पर व्यापक क्रूरता हुई और राष्ट्र के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने उस समय को भी याद किया जब बाबा साहेब अंबेडकर ने नए भारतीय संविधान में किए गए वादे के अनुसार पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा कार्रवाई न किए जाने के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जगजीवन राम जी, चौधरी चरण सिंह जी और सीताराम केसरी जी जैसे अन्य प्रमुख नेताओं पर किए गए अत्याचारों पर भी प्रकाश डाला।

दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का हवाला देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें ऐसे धर्म से जुड़े होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र और विविधता केवल हिंदू समुदाय की सहिष्णुता और एकता की भावना के कारण ही पनपी है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि आज हिंदू समुदाय पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।

पिछले 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए कई सुधार

भारत के सशस्त्र बलों की वीरता और ताकत की सराहना करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। साथ ही, उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों को हर चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक और सुसज्जित बनाने का उल्लेख किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। 'थिएटर कमांड' की स्थापना के महत्त्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति के बाद इस लंबे समय से लंबित सैन्य संगठनात्मक ढांचे को स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारे सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सशस्त्र बलों को युवा होना चाहिए और हमारे बलों में युवाओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर मामला है और सरकार सशस्त्र बलों को 'युद्ध के योग्य' बनाने के लिए समय पर सुधार कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि चाहे वह हथियार हों या तकनीक, युद्ध के परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसलिए झूठे आरोपों और प्रत्यारोपों के बावजूद ऐसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे बलों को मजबूत करने की सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न भ्रष्टाचार और घोटालों ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को मजबूत करने में बाधा डाली थी।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने पिछले कार्यकाल में 'वन रैंक, वन पेंशन' योजना को लागू किया

- भारत की जनता ने पिछले 10 वर्षों के हमारी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा जताया है और हमें तीसरी बार सुशासन जारी रखने का अवसर दिया है
- लोगों ने 'जन सेवा ही प्रभु सेवा' यानी यानी मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, के विश्वास के साथ नागरिकों की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता देखी है
- भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लोगों ने पुरस्कृत किया
- हमने तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण; तुष्टीकरण के बजाय संतृप्ति (परिपूर्णता) के लिए काम किया
- 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास, अपेक्षाएं और भरोसा विकास के लिए प्रेरक शक्ति बन गया है
- 'राष्ट्र प्रथम' ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है
- जब कोई देश विकसित होता है, तो आने वाली पीढ़ियों के सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखी जाती है
- तीसरे कार्यकाल में हम तीन गुनी गति से काम करेंगे, तीन गुनी ऊर्जा लगाएंगे और तीन गुना परिणाम देंगे

था जो लंबे समय से रुकी हुई थी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की कठिनाइयों के बावजूद उनकी सरकार ने ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये दिए थे।

सरकार युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर कर रही काम

हाल ही में हुए पेपर लीक पर चिंता जताते हुए श्री मोदी ने देश के युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहद गंभीर है और युवाओं तथा राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नीट-यूजी पेपर लीक मामले में देशभर में कई गिरफ्तारियां की गई हैं। श्री मोदी ने कहा, "केंद्र सरकार पहले ही सख्त कानून बना चुकी है। पूरी स्क्रीनिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 10 वर्षों में विकास सरकार का सबसे बड़ा संकल्प रहा है।" उन्होंने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, हर घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने, हर गरीब को पक्का घर देने, सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मजबूत बनाने, देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने, भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने, बुनियादी ढांचे के विकास को आधुनिक बनाने, विकसित भारत में नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, कौशल विकास को सशक्त बनाने और युवाओं के भविष्य को आकार देने के संकल्पों पर प्रकाश डाला। हाल के एक अध्ययन का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि पिछले 18 वर्षों के दौरान निजी उद्योग में रोजगार सृजन में रिकॉर्ड संख्या देखी गई है।

भारत दुनिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण

डिजिटल इंडिया आंदोलन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में खड़ा है। जी-20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया के विकसित देश भी हमारे डिजिटल आंदोलन से चकित हैं।

श्री मोदी ने भारत की प्रगति के साथ प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों में बढ़ोतरी पर भी बात की और उन लोगों को चेतावनी दी जो देश की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं और भारत के लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "ऐसा लगता है कि हर प्रयास में संदेह पैदा करके और इसकी नींव को कमजोर करके भारत की प्रगति को कमजोर करने का एक मजबूत प्रयास किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों को स्रोत से ही खत्म किया जाना चाहिए।"

उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर पूरे सदन द्वारा गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया और नागरिकों से ऐसी ताकतों से सतर्क रहने का भी आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा, "भारत कभी भी राष्ट्र विरोधी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा।"

श्री मोदी ने दोहराया कि दुनिया भारत की प्रगति को बहुत गंभीरता से ले रही है और सभी पेचीदगियों पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने संकल्पों को पूरा करने और एक विकसित भारत बनाने के लिए सदन के प्रत्येक सदस्य के योगदान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सदस्यों से देश के कल्याण में भरोसे के साथ आगे आने का आग्रह किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और नागरिकों के सपनों और उम्मीदों को पूरा करना चाहिए।" उन्होंने वर्तमान युग में सकारात्मक राजनीति के महत्त्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "आइए, हम सुशासन, वितरण और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर प्रतिस्पर्धा करें।"

भाषण के दौरान श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ दुर्घटना में पीड़ितों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि राज्य सरकार खोज और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई है, वहीं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी पीड़ितों को सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं।

श्री मोदी ने पहली बार संसद के लिए चुने गए सदस्यों को विशेष रूप से बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने संबोधन का समापन किया और धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचारों और योगदान के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया। ■

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का जवाब

विकसित भारत 140 करोड़ नागरिकों का मिशन है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। श्री मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक अभिभाषण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगभग 70 सदस्यों ने अपने विचार रखे और प्रधानमंत्री ने उन सदस्यों को धन्यवाद दिया

देश की लोकतांत्रिक यात्रा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 60 वर्षों के बाद भारत के मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार किसी सरकार को वापस लाया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मतदाताओं के निर्णय को कम आंकने के विपक्ष के कदम की निंदा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि विपक्ष ने भारी मन से अपनी हार और हमारी जीत को स्वीकार किया है।

प्रधानमंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने शासन का केवल एक तिहाई यानी 10 वर्ष ही पूरा किया है और अभी दो तिहाई यानी 20 वर्ष बाकी हैं। श्री मोदी ने कहा, "भारत के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में देश की सेवा करने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का पूरे दिल से समर्थन किया है और आशीर्वाद दिया है।" उन्होंने नागरिकों के फैसले पर गर्व व्यक्त किया, जिन्होंने दुष्प्रचार को हराया, काम-काज को प्राथमिकता दी, भ्रम की राजनीति को नकारा और विश्वास की राजनीति पर जीत की मुहर लगाई।

भारत का संविधान 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है

भारत का संविधान अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसे देखते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह एक विशेष स्थिति है, क्योंकि भारत की संसद भी 75 वर्ष पूरे कर रही है, जो इसे एक सुखद संयोग बनाता है। श्री मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान की प्रशंसा की और कहा कि जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत में कभी राजनीतिक परिवार से जुड़ा नहीं था, उन्हें संविधान में निहित अधिकारों के कारण देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा, "यह बाबा साहेब अंबेडकर का दिया संविधान ही है, जिसने मेरे जैसे लोगों को, जिनका कोई राजनीतिक वंश नहीं है, राजनीति में प्रवेश करने और इस मुकाम तक पहुंचना संभव किया है।" उन्होंने आगे कहा कि अब, जब लोगों ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है, तो सरकार लगातार तीसरी बार आई है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान केवल लेखों का संकलन नहीं है, बल्कि इसकी भावना और छाप अत्यंत मूल्यवान है।

श्री मोदी ने याद दिलाया कि जब उनकी सरकार ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, तो इसका कड़ा विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाने के उनके फैसले से स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं के बीच संविधान की भावना को और अधिक प्रसारित करने, संविधान में कुछ प्रावधानों को क्यों और कैसे शामिल किया गया और कैसे हटाया गया, इस पर चर्चा और विचार-विमर्श करने में मदद मिली है। श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि संविधान के विभिन्न पहलुओं पर हमारे छात्रों के बीच निबंध, वाद-विवाद और तात्कालिक भाषण जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से संविधान के प्रति आस्था बढ़ेगी और समझ विकसित होगी। उन्होंने कहा कि संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि संविधान अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए उनकी सरकार ने इसे देशव्यापी उत्सव सुनिश्चित करने के लिए 'जन उत्सव' के रूप में मनाने की योजना बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि वे यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे कि संविधान की भावना और उद्देश्य को लेकर देश के हर कोने

में जागरूकता हो।

भावी सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिला यह जनादेश

श्री मोदी ने मतदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उनकी सरकार को तीसरी बार वोट दिया है ताकि 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के माध्यम से विकास और निर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। श्री मोदी ने अपनी चुनावी जीत को न केवल पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर नागरिकों की स्वीकृति की मुहर बताया, बल्कि उनके भावी सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक जनादेश भी बताया। उन्होंने कहा, "इस देश के लोगों ने हमें अपने भविष्य के संकल्पों को साकार करने का अवसर दिया है।"

श्री मोदी ने याद दिलाया कि देश ने पिछले दस वर्षों में वैश्विक अस्थिरता और महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को दसवें से पांचवें स्थान पर पहुंचते देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनादेश अर्थव्यवस्था को वर्तमान पांचवें स्थान से तीसरे स्थान पर ले जाने के लिए है। उन्होंने इस जनादेश को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया।

श्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में हुए विकास की गति और दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि अगले पांच वर्षों में सरकार लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि सुशासन की मदद से हम इस युग को ऐसे युग में बदलना चाहते हैं, जहां बुनियादी जरूरतों की कहीं कोई कमी न रह पाए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश से गरीबी हटाने के लिए अगले पांच साल महत्त्वपूर्ण हैं और पिछले 10 वर्षों के अनुभवों के आधार पर गरीबी के खिलाफ खड़े होने और इसे दूर करने के लिए गरीबों की सामूहिक क्षमताओं में विश्वास व्यक्त किया।

लोगों के जीवन के हर पहलू पर भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस संभावना का वैश्विक परिदृश्य पर भी अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अगले पांच वर्षों में भारतीय स्टार्टअप और कंपनियों के वैश्विक पुनरुत्थान और विकास इंजन के रूप में उभर रहे टियर 2 और टियर 3 शहरों के बारे में बात की।

वर्तमान सदी को प्रौद्योगिकी संचालित सदी बताते हुए श्री मोदी ने सार्वजनिक परिवहन जैसे कई नए क्षेत्रों में नई तकनीक के इस्तेमाल की बात की। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि छोटे शहर चिकित्सा, शिक्षा या नवाचार जैसे क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

किसान, गरीब, नारीशक्ति और युवा

किसान, गरीब, नारीशक्ति और युवा के चार स्तंभों को मजबूत करने के महत्त्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों पर सरकार का ध्यान भारत के विकास की यात्रा में महत्त्वपूर्ण है।

कृषि और किसानों के लिए सुझाव देने के लिए संसद सदस्यों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए कृषि को आकर्षक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को याद किया। उन्होंने ऋण, बीज, सस्ती उर्वरक, फसल बीमा, एमएसपी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री मोदी ने कहा कि हमने किसानों को हर स्तर पर सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से बीज से लेकर बाजार तक एक मजबूत प्रणाली प्रदान करने का भरसक प्रयास किया है।

पिछले 6 वर्षों में 10 करोड़ किसानों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का लाभ

श्री मोदी ने किसान क्रेडिट कार्ड के लाभों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्रेडिट कार्ड ने छोटे किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुआरों और पशुपालकों को भी दिया गया है। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया और पीएम किसान सम्मान निधि पर प्रकाश डाला, जिससे पिछले 6 वर्षों में 10 करोड़ किसानों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। श्री मोदी ने पिछली सरकारों में ऋण माफी योजनाओं की विफलता और विश्वसनीयता की कमी को भी इंगित किया और वर्तमान शासन की किसान कल्याण योजनाओं को रेखांकित किया।

विपक्ष के बहिर्गमन के बाद अपना भाषण जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने सदन के अध्यक्ष के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि मैं लोगों का सेवक होने के लिए बाध्य हूं। मैं अपने जीवन के हर पल लोगों के प्रति जवाबदेह हूं। उन्होंने सदन की परंपराओं का अनादर करने के लिए विपक्ष की आलोचना भी की।

उर्वरकों के लिए आजादी के बाद से सबसे अधिक 12 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी

श्री मोदी ने जोर देते हुए बताया कि उनकी सरकार ने गरीब किसानों को उर्वरकों के लिए आजादी के बाद से सबसे अधिक 12 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार ने न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में रिकॉर्ड वृद्धि की घोषणा की, बल्कि उनसे खरीद में भी नए रिकॉर्ड बनाए। पिछली सरकार से तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में धान और गेहूं के किसानों को 2.5 गुना अधिक धन दिया है। उन्होंने कहा कि हम यहीं नहीं रुकना चाहते। अगले पांच वर्षों तक हम नए क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वर्तमान में खाद्य भंडारण का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय व्यवस्था के तहत लाखों अन्न भंडार बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि बागवानी कृषि का एक महत्त्वपूर्ण

क्षेत्र है और उनकी सरकार इसके सुरक्षित भंडारण, परिवहन और बिक्री के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास यात्रा के दायरे का लगातार विस्तार किया है। उन्होंने रेखांकित किया कि नागरिकों को सम्मान का जीवन प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक जो लोग उपेक्षित रहे, आज उनकी न केवल देखभाल की जाती है, बल्कि उनका सम्मान भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भाई-बहनों की समस्याओं को मिशन मोड में और सूक्ष्म स्तर पर दूर किया जा रहा है, ताकि वे दूसरों पर कम से कम निर्भर रहते हुए सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। अपनी सरकार की समावेशी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने समाज के उपेक्षित वर्ग ट्रांसजेंडरों के लिए कानून लागू करने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि आज पश्चिमी देश भी भारत की प्रगतिशील प्रकृति को गर्व से देखते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने अब ट्रांसजेंडरों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार भी प्रदान किए हैं।

'जन मन योजना' के लिए 24 हजार करोड़ रुपये आवंटित

इसी तरह, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया गया है। श्री मोदी ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए भी कदम उठाए जाने का उल्लेख किया, जिसके तहत 'जन मन योजना' के लिए 24 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि सरकार वोट की राजनीति के बजाय विकास की राजनीति कर रही है।

श्री मोदी ने भारत के विश्वकर्माओं का भी जिक्र किया जिन्होंने भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने करीब 13 हजार करोड़ रुपये की मदद से व्यावसायिकता पैदा करके और कौशल विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराकर उनके जीवन को बदल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री 'स्वनिधि योजना' का भी जिक्र किया, जिसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बैंक से ऋण लेने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि चाहे गरीब हों, दलित हों, पिछड़े समुदाय हों, आदिवासी हों या महिलाएं हों, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है।

गरीबों को मिले 4 करोड़ घर

श्री मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास के भारतीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसकी ओर देश सिर्फ नारे के तौर पर नहीं बल्कि अटूट प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। महिला स्वास्थ्य के संबंध में श्रीमती सुधा मूर्ति के हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने परिवार में मां के महत्त्व को रेखांकित किया। श्री मोदी ने महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और तंदुरुस्ती पर प्राथमिकता से ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उन्होंने शौचालय, सैनिटरी पैड, टीकाकरण, रसोई गैस को इस दिशा में प्रमुख उपायों के रूप में उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गरीबों को सौंपे गए 4 करोड़ घरों में से अधिकांश महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं। उन्होंने 'मुद्रा' और 'सुकन्या समृद्धि योजना' जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, उन्हें स्वतंत्र बनाया है और निर्णय लेने में उनकी आवाज को बुलंद किया है। श्री मोदी ने बताया कि अब तक छोटे गांवों में स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि सरकार वर्तमान कार्यकाल में उनकी संख्या को 3 करोड़ तक बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि उनकी सरकार का प्रयास महिलाओं को हर नए क्षेत्र में अग्रणी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि हर नई तकनीक सबसे पहले महिलाओं तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज 'नमो ड्रोन दीदी' अभियान गांवों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिसमें महिलाएं सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन चलाने वाली महिलाओं को 'पायलट दीदी' कहा जाता है और इस तरह की मान्यता महिलाओं के लिए एक प्रेरणा शक्ति है। महिलाओं के मुद्दों का राजनीतिकरण करने की प्रवृत्ति और चयनात्मक रवैये की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चिंता व्यक्त की।

देश की नई वैश्विक छवि पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 'अगर-मगर' का दौर खत्म हो गया है क्योंकि भारत विदेशी निवेश का स्वागत कर रहा है जो देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर युवा अपनी क्षमता और प्रतिभा का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आज की जीत उन निवेशकों के लिए उम्मीद लेकर आई है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन की उम्मीद कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शिता के मामले में आज भारत एक आशाजनक देश के रूप में उभर रहा है।

आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार

प्रधानमंत्री ने 1977 के लोकसभा चुनावों के समय को याद किया जब प्रेस और रेडियो पर अंकुश लगा दिया गया था और लोगों की आवाज दबा दी गई थी। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि मतदाताओं ने तब भारत के संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मतदान किया था, जबकि आज, संविधान को बचाने की इस लड़ाई में भारत के लोगों की पहली पसंद मौजूदा सरकार है। श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान देश पर किए गए अत्याचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधनों के साथ-साथ एक दर्जन अन्य अनुच्छेदों का भी

उल्लेख किया, जिन्हें आपातकाल के दौरान संशोधित किया गया था और इस तरह संविधान की भावना के साथ छेड़छाड़ की गई। श्री मोदी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) की नियुक्ति की भी आलोचना की, जिसके पास कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को पलटने का अधिकार था और स्थापित प्रोटोकॉल के बावजूद एक ही परिवार को तरजीह दी गई। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौर पर चर्चा से बचने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए टालमटोल के तरीकों की भी आलोचना की।

श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल का दौर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र, संविधान और मानवता से जुड़ा था। आपातकाल के दौरान जेल में बंद तत्कालीन विपक्षी नेताओं पर हुए अत्याचारों की ओर इशारा करते हुए श्री मोदी ने स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी का जिक्र किया, जो रिहाई के बाद पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। आपातकाल के दौरान मुजफ्फरनगर और तुर्कमान गेट में अल्पसंख्यकों की स्थिति को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने गहरे दु:ख के साथ कहा कि आपातकाल के बाद घर छोड़कर गए कई लोग कभी वापस नहीं लौटे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक मिशन है

श्री मोदी ने विपक्ष के कुछ समूहों द्वारा भ्रष्टाचारियों को बचाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। विपक्षी दलों के विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न घोटालों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की भी आलोचना की। उन्होंने पिछली सरकारों में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के उदाहरण भी दिए। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मेरे लिए एक मिशन है। श्री मोदी ने 2014 में अपनी नई सरकार के आगमन के समय गरीबों के प्रति समर्पण और भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट के दोहरे वादों को याद किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी 'गरीब कल्याण योजना' और भ्रष्टाचार के खिलाफ नए कानूनों जैसे कालेधन, बेनामी के खिलाफ कानून और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के प्रावधानों और प्रत्येक पात्र लाभार्थी को लाभ के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने में प्रकट होता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मैंने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट दी है।

हाल ही में हुए पेपर लीक पर राष्ट्रपति की चिंता को दोहराते हुए श्री मोदी ने युवाओं को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार देश के भविष्य के साथ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उन्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को किसी भी तरह के संदेह में न रहना पड़े और वे आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें।

जम्मू-कश्मीर के लोगों ने संविधान में दिखाई अपनी अटूट आस्था

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के मतदान के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पिछले चार दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में मतदान किया। उन्होंने जनादेश की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भारत के संविधान, लोकतंत्र और चुनाव आयोग को स्वीकृति दी है। श्री मोदी ने इसे देश के नागरिकों के लिए बहुप्रतीक्षित क्षण बताया। जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में जम्मू-कश्मीर में कई बंद, विरोध प्रदर्शन, विस्फोट और आतंकी गतिविधियों ने लोकतंत्र को ग्रहण लगा दिया था। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के लोगों ने संविधान में अपनी अटूट आस्था दिखाई है और अपना भविष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि एक तरह से हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई के अंतिम चरण में हैं। हम बाकी आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जम्मू-कश्मीर के लोग इस लड़ाई में हमारी मदद और मार्गदर्शन कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे का हुआ अभूतपूर्व विकास

श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर तेजी से देश की प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विकास का उल्लेख किया। उन्होंने क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के प्रयासों के दीर्घकालिक प्रभाव की भी उम्मीद जताई, क्योंकि राज्यों के बीच सीमा विवादों को आम सहमति के साथ सार्थक तरीके से निपटाया जा रहा है।

राज्यसभा के पिछले सत्र में मणिपुर के बारे में अपने विस्तृत भाषण को याद करते हुए श्री मोदी ने दोहराया कि सरकार मणिपुर में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अशांति के दौरान और उसके बाद 11,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं और 500 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि मणिपुर में शांति की उम्मीद बढ़ रही है। श्री मोदी ने सदन को बताया कि आज मणिपुर में स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और अन्य संस्थान सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास में भी किसी तरह की बाधा नहीं आई है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मणिपुर में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गृह मंत्री ने स्वयं मणिपुर में रहकर शांति प्रयासों का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान खोजने और शांति सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी काम पर लगाया गया है।

श्री मोदी ने मणिपुर में अभी बाढ़ की भयावह स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सदन को बताया कि मणिपुर में बाढ़ राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहत प्रयासों में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और पार्टी लाइन से हटकर काम करना सभी हितधारकों का कर्तव्य है। श्री मोदी ने असंतुष्टों से मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को भड़काने और उसे और अधिक खतरे में डालने से बचने का अनुरोध किया। उन्होंने सदन को बताया कि मणिपुर में सामाजिक संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका एक लंबा इतिहास रहा है। मणिपुर में आजादी के बाद से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 1993 से मणिपुर में 5 साल तक चले सामाजिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्थिति को समझदारी और धैर्य के साथ संभालने की जरूरत है। उन्होंने मणिपुर में सामान्य स्थिति और शांति सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में मदद करने के लिए सभी समान विचारधारा वाले लोगों को आमंत्रित किया।

सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने संघवाद के महत्त्व को अनुभव से सीखा है, क्योंकि लोकसभा में कदम रखने और प्रधानमंत्री बनने से पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। श्री मोदी ने 'सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद' को मजबूत करने के अपने रुख को रेखांकित किया और वैश्विक मंच पर राज्य और उसकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए देश के हर राज्य में महत्त्वपूर्ण जी-20 कार्यक्रम आयोजित करने का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड महामारी के दौरान राज्य और केंद्र के भीतर रिकॉर्ड संख्या में चर्चाएं और विचार-विमर्श हुए।

श्री मोदी ने बताया कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अगली क्रांति का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने भारत के राज्यों को विकास, सुशासन, नीति निर्माण, रोजगार सृजन और विदेशी निवेश आकर्षित करने में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जब दुनिया भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो भारत के हर राज्य के पास अवसर है। उन्होंने सभी राज्यों से भारत की विकास गाथा में योगदान देने और इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने पूर्वोत्तर में असम का उदाहरण दिया जहां सेमीकंडक्टर से संबंधित काम तेजी से हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को 'मोटा अनाज वर्ष' घोषित किए जाने के बारे में बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह भारत के छोटे किसानों की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने राज्यों से मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने और इसे वैश्विक बाजार में उतारने के लिए रोडमैप बनाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि मोटे अनाज का उपयोग दुनिया के पोषण बाजार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और कुपोषित आबादी वाले क्षेत्रों में मुख्य भोजन बन सकता है।

श्री मोदी ने राज्यों से ऐसी नीतियां और कानून बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जिनसे नागरिकों के बीच 'जीवन की सुगमता' बढ़े। उन्होंने पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, तहसील या जिला परिषद् सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाने की आवश्यकता जताई और इस लड़ाई में राज्यों से एकजुट होने का आह्वान किया।

वर्तमान सदी भारत की सदी

21वीं सदी का भारत बनाने के लिए सरकार के निर्णय लेने, वितरण और शासन मॉडल में दक्षता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों की गति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षता व्यवस्था में पारदर्शिता लाती है, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, जीवन को आसान बनाने को बढ़ावा मिलता है और 'अगर-मगर' की स्थिति खत्म होती है। श्री मोदी ने नागरिकों के जीवन में सरकार के हस्तक्षेप को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही जरूरतमंदों को सरकार की ओर से मदद देते रहने पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सभी राज्यों को आगे आकर इससे लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने कहा कि सभी को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन मूलभूत लक्ष्यों को राजनीतिक इच्छाशक्ति से प्राप्त किया जा सकता है और हर राज्य आगे बढ़कर इन लक्ष्यों तक पहुंचने में सहयोग करेगा।

श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सदी भारत की सदी होने जा रही है और हम इस अवसर को गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि भारत ने कई मौके गंवाए, जबकि इसी तरह की स्थिति वाले कई देश विकसित हो गए हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि सुधारों से बचने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निर्णय लेने की अधिक शक्ति मिलने से प्रगति और विकास निश्चित रूप से होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत 140 करोड़ नागरिकों का मिशन है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत में संभावनाओं को देखते हुए निवेश करने के लिए तैयार है और भारत दुनिया की पहली पसंद है। उन्होंने राज्यों से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया।

श्री मोदी ने राष्ट्रपति को उनके मार्गदर्शन और अभिभाषण में उठाए गए मुद्दों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने संबोधन का समापन किया। ■

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन

ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 15 प्रतिशत है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने दो जुलाई, 2024 को राज्यसभा में माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए। राज्य सभा में बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह अभिभाषण समग्रता में है, होलिस्टिक है और विकसित भारत की विकास यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में बहुत चिंतन किया गया है। यह हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है, जिसे हम सब लोग 'विकसित भारत' को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन की मुख्य बातें:

मैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर धन्यवाद देने के लिए और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए इस अपने वक्तव्य को रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं राष्ट्रपति अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापन में अपना वक्तव्य रख सकूं।

समग्रता में है अभिभाषण

यह जो अभिभाषण है जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सेंट्रल हॉल में अपने पार्लियामेंट के कक्ष में हम सबके सामने रखा, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे विकास यात्रा की एक कहानी और एक रोड मैप है। इसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी ने हम सबके सामने रखा है और मैं यह कह सकता हूं कि यह जो अभिभाषण है यह समग्रता में है, होलिस्टिक है, और यह विकसित भारत की विकास यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में बहुत चिंतन करके उस वक्तव्य में बहुत डिटेल से लिखा गया है। यह हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है जिसे हम सब लोग 'विकसित भारत' को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की पॉलिसी और कार्यक्रम जो उद्धृत किए हैं, वे दोनों बातों को प्रतिलक्षित करते हैं। एक तो वे प्रतिलक्षित करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और दूसरा, किस तरीके से यह कार्यक्रम और नीतियां देश को विकसित भारत बनाने में दूरगामी प्रभाव छोड़ रही हैं उसको भी उद्धृत करता है, यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम 'अमृत काल' में प्रवेश कर चुके हैं। जब हम अमृत काल में प्रवेश किए हैं, तो आगे हमारे सामने 25 साल की यात्रा है, जिस यात्रा में हम सब लोगों ने अपने देश को डेवलप नेशन, विकसित भारत, डेवलप भारत, इस संकल्प को आगे बढ़ाने का तय किया है।

सरकार की नीतियों का सब दूरगामी प्रभाव हम सब लोगों को दिख रहा है और दिखने लगा है। यह ऐतिहासिक पल, 'अमृत काल' का, हम सबके लिए सच में बहुत ही सौभाग्यपूर्ण स्थिति है जब हम इस अमृत काल में अपने आप को जोड़ रहे हैं और विकसित भारत की यात्रा में हम सब लोग भी शामिल हो रहे हैं।

अभी-अभी हम सब लोगों ने 21 जून को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था 10 साल पहले कि भारत की कोई यू.एन जनरल असेंबली में कोई प्रस्ताव लेकर आएगा और उस प्रस्ताव को एकमत से 177 देश अपना साथ देंगे और वह

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बन जाएगा। आज हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है कि भारत और दुनिया 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और भारत को योग का लीडर मान रही है।

आज अंतरराष्ट्रीय मिलेट दिवस सारी दुनिया मना रही है। श्री अन्न की तरफ हम अग्रसर हुए हैं और जब हम श्री अन्न की तरफ अग्रसर हुए हैं, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उनको इसका बहुत दूरगामी प्रभाव में लाभ मिलने वाला है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।

अभी पिछले साल देश जी-20 के उत्सव का साक्षी रहा है। चाहे कोई प्रदेश विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कहीं किसी और पार्टी की सरकार हो, चाहे कहीं हमारी पार्टी की सरकार हो, सारे देश ने जी-20 को अपने तरीके से आत्मसात् किया और जी-20 एक नेशनल इवेंट और नेशनल फेस्टिवल बन गया। लगभग 200 मीटिंग दिल्ली में नहीं हुईं, 200 मीटिंग देश के कोने-कोने में हुईं और 75 स्थानों में हुईं। एक तरीके से दुनिया ने भी भारत के दर्शन किए। जी-20 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से हुआ। भारत के नेतृत्व में, भारत के निवेदन पर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ा गया। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।

> इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि "द इंडियन इकॉनमी इज द ओनली ब्राइट स्पॉट।" अगर कोई आशा की किरण है, तो वह इंडियन इकॉनमी है। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं, "इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013।" मूडीज कहते हैं, "GDP ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीजड टू 8 परसेंट फॉर द ईयर 2024"

वैश्विक आशा की किरण 'भारतीय अर्थव्यवस्था'

दुनिया की हर इकॉनमी डिस्टर्ब है। चाहे वो अमेरिका, चाहे वो यूरोप नेशन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो जापान, चाहे वो जर्मनी, कोई भी देश आज उनकी आर्थिक स्थिति मुसीबत में है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि "द इंडियन इकॉनमी इज द ओनली ब्राइट स्पॉट।" अगर कोई आशा की किरण है, तो वह इंडियन इकॉनमी है। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं, "इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013।" मूडीज कहते हैं, "GDP ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीजड टू 8 परसेंट फॉर द ईयर 2024।"

हम सब लोग जानते हैं कि 10 साल पहले भारत की अर्थनीति 11वें पोजीशन पर थी और आज भारत उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थ शक्ति बनेगा।

हमारा ग्रोथ रेट, आफ्टर कोविड, 2021-22 में 9.1 परसेंट, 2022-23 में 7 परसेंट, 2023-24 में 8.2 परसेंट और आपको जानकर खुशी होगी और हम सबको खुशी होगी कि भारत आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन 15 परसेंट है। इंडियन इकॉनमी और हम, जैसा मैंने कहा कि हम तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी की तरफ अग्रसर होने के लिए लगे हैं।

अगर हम सेक्टर्स की बात करें, आज फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया नंबर 2 पर है। आज दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है। भारत सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिकन्स भी आज भारत की दवाई को ले रहे हैं और ओपनली कहते हैं कि भारत की दवाई हमें अच्छी पड़ती है। और दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है, तो भारत। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। स्टील में हम नंबर 2 पर हो कर के खड़े हो गए हैं और इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल्स से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी बढ़े ही हैं।

भारत आईटी का हब

10 साल पहले, 97% मोबाइल्स बाहर से आते थे। हमारे पास जो मोबाइल होता था, "मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन वियतनाम" होता था। आज, 97% मोबाइल्स भारत में बन रहे हैं। आईटी में तो भारत हब बन चुका है। दुनिया को भारत का आईटी का लोहा मानना पड़ा है और टूरिज्म में भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। इसलिए सर्विस सेक्टर में हम अपने आप को और जॉब अपॉर्चुनिटी को देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं।

एग्रीकल्चर के सेक्टर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और फिशरी बेस्ड इंडस्ट्री में हमारा ब्लू रेवोल्यूशन है। इसको हमने प्रायोरिटी दी है और इस प्रायोरिटी के साथ-साथ हमने गांव को जोड़ने का काम किया है। विकास की दृष्टि से विलेजेस को जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज एक नेटवर्क फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) का बन रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे एफ.पी.ओ के साथ-साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन (PAC's) के माध्यम से हमारे लगभग एक लाख पैक्स हैं, जो लगभग 13 करोड़ फार्मर्स तक की पहुंच बना चुके हैं।

आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुधारें, 18वीं किस्त में पहुंचाया गया है और अभी-अभी कुछ दिन पहले 20 करोड़ रुपए की किस्त पहुंचाई गई है और यह रुकने वाली नहीं है, यह सतत चलने वाली है। किसानों के बारे में चिंता करने वाली है। हम वन टाइम रिलीफ देने वाले नहीं हैं। हम हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। किसान जब तक खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके साथ खड़े रहने वाले हैं। ■

‘लोकतंत्र का काला दिवस’ कार्यक्रम

कांग्रेस ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया : जगत प्रकाश नड्डा

देश एकजुट होकर आपातकाल के खिलाफ खड़ा हुआ

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में ‘लोकतंत्र का काला दिवस’ कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस द्वारा आपातकाल लगाकर लोगों पर किए गए अत्याचार तथा कांग्रेस एवं विपक्ष द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष, राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री शिवप्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री श्री राधा मोहन अग्रवाल एवं राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी डॉ. संजय मयूख उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि 25 जून, 1975 को देश के प्रजातंत्र के गले को घोंटकर देश में आपातकाल लगाया गया था और इसको जनता के समक्ष लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज काला दिवस कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कांग्रेस ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया। देश एकजुट होकर आपातकाल के खिलाफ खड़ा हुआ और सबने डटकर इसका विरोध किया था। आज देश में आपातकाल के दौरान दुःख के दिनों के 50 वर्ष हो गए हैं। जनता कल्पना नहीं कर सकती एक रात में 9 हजार लोगों को जबरन उठा लिया गया जिसमें मोरारजी देसाईजी, मोहन धारियाजी, अटल बिहारी वाजपेयीजी, लालकृष्ण आडवाणीजी जैसे नेताओं की लंबी श्रृंखला है, जिनको 25 जून, 1975 को हिरासत में ले लिया गया और इन नेताओं को एक दिन या दो दिन नहीं, बल्कि 19 महीनों से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था। इन नेताओं का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा और मजबूती के लिए आवाज उठाई थी।

श्री नड्डा ने कहा कि 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया और न्यायालय ने अनुचित तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया था और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संविधान को बदलकर इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास किया। जिसके बाद पूरा देश उद्वेलित हो गया और इस उद्वेलना को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 की रात को आपातकाल की घोषणा की और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने उस समय अपना योगदान दिया था। लगभग 1 लाख 40 हजार लोग आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA) और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स (DIR) के तहत लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से लगभग 75 से 80 हजार लोग भारतीय स्वयंसेवक के लोग थे।

श्री नड्डा ने कहा कि आज विपक्ष प्रजातंत्र की दुहाई देकर संविधान की रक्षा की बातें कर रहा है जबकि कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को दरकिनार कर जस्टिस अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया। कांग्रेस सरकार ने जस्टिस खन्ना को दरकिनार कर जस्टिस बेग को भी देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली कांग्रेस ने सूडो-सेक्युलरिज्म का उदाहरण प्रस्तुत किया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले में निर्वाह निधि देने का निर्णय किया था, मगर 21वीं सदी की ओर देखने वाले राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके इस निर्णय को पलटने का कार्य किया था। विपक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना के खिलाफ खड़ा है। ■

कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया तथा जो भी व्यक्ति तत्कालीन कांग्रेस सरकार से असहमत हुआ, उसे प्रताड़ित एवं परेशान किया गया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा "आज का दिन उन सभी महान पुरुषों एवं महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया।

आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को समाप्त किया और भारत के संविधान को रौंदने का कार्य किया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है।"

उन्होंने कहा कि सत्ता पर आसीन रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और

देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया। इस दौरान कांग्रेस से असहमत होने वाले हर व्यक्ति को प्रताड़ित एवं परेशान किया गया। सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए सामाजिक रूप से प्रतिगामी नीतियां लागू की गईं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लगाया'। प्रधानमंत्री ने कहा, "जिन लोगों ने आपातकाल लगाया, उन्हें संविधान के प्रति अपनी सद्भावना दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लगाया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने वाला विधेयक पारित किया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया।"

यही नहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह पार्टी दिखावे के ज़रिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छुपा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिखा, 'जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया था, वह उसी पार्टी में भी मौजूद है जिसने इसे लगाया था। वे दिखावे के ज़रिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छुपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देख लिया है और इसीलिए उन्होंने उन्हें बार-बार नकारा है'।

जामनगर (गुजरात) में 1974 में अभाविप द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी; यह कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने से एक साल पूर्व आयोजित किया गया था।

फोटो सौजन्य: एक्स/@modiarchive

भाजपा, केरल प्रदेश विस्तारित कार्यकारिणी बैठक, तिरुवनंतपुरम

केरल की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जुलाई, 2024 को केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदेश भाजपा विस्तारित कार्यकारिणी बैठक के समापन-सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एवं एनडीए ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों ने भ्रष्टाचार बढ़ाया और देश विरोधी लोगों को ताकत प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान केरल प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री के. सुरेन्द्रन, केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, राष्ट्रीय मंत्री श्री अब्दुल्लाह कुट्टी व श्री अनिल एंटनी, वरिष्ठ नेता श्री ओ. राजगोपाल व श्री कुंभनम राजशेखरन सहित प्रदेश भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि केरल कठिन परिश्रम, विनम्रता और समर्पण के लिए जाना जाता है और यह भाजपा कार्यकर्ताओं में भी दिखता है। जिस समर्पण के साथ भाजपा कार्यकर्ता विचारधारा को लेकर विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उसी का फल है कि आज 60 वर्षों के इतिहास में देश में पहली बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी है। आजादी के बाद पहली बार लोकसभा में केरल से भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमल खिला दिया है।

जिस समर्पण के साथ भाजपा कार्यकर्ता विचारधारा को लेकर विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उसी का फल है कि आज 60 वर्षों के इतिहास में देश में पहली बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी है

उन्होंने कहा कि जब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पुनः एनडीए सरकार बनी, जो स्थिरता और निरंतरता का संदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में 178 विधानसभा सीटों में से 78 सीटें जीतकर और लोकसभा में 21 में से 20 सीटें जीतकर सरकार बनाई। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। कई लोग एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के साथ देश के लगभग सभी राज्यों में खुद को स्थापित करके दिखाया है। तेलंगाना में भाजपा की सीटें डबल हो गई हैं और तेलंगाना में भी भाजपा जीत कर आएगी। अरुणाचल प्रदेश में भी 60 में से 46 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए एवं भाजपा ने कर्नाटक में भी स्वीप किया और तमिलनाडु में भाजपा का वोट प्रतिशत 11.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तमिलनाडु में भी भाजपा बेहतर की स्थिति और बेहतर होगी। केरल के त्रिशूर में भाजपा ने 75 हजार के बड़े अंतर से चुनाव जीता और अटिंगल व तिरुवनंतपुरम में भी भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। आने वाले समय में भाजपा केरल विधानसभा में भी कमल खिलाएगी। आज केरल के 6 नगर निगमों में भी भाजपा ने बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी को तिरुवनंतपुरम में 36 प्रतिशत वोट शेयर प्राप्त हुआ है।

श्री नड्डा ने कहा कि केरल में भाजपा कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में भी परिश्रम, लगन और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। केरल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान पर खेलकर राज्य में कमल खिलाया है। कांग्रेस के लोग बड़ी जीत की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने सांसदों के आंकड़े को जोड़ ले, तब भी 2024 में उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीती हैं। कांग्रेस को 13 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली और कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों की कारण ही अपनी सीटों में बढ़ोतरी कर पाई है। कांग्रेस परजीवी पार्टी बन गई है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 64 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई, जिसमें से 62 सीटें भाजपा ने जीती और कांग्रेस महज 2 सीटें ही निकाल पाई। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का स्ट्राइक रेट 26 प्रतिशत है, जबकि कांग्रेस जहां परजीवी बनकर चुनाव लड़ती है, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50 प्रतिशत हो जाता है। कांग्रेस बैसाखियों पर चलने वाली पार्टी है।

उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी का साथ नहीं मिला, इसलिए स्वयं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी चुनाव हार गए और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। केरल में डी. राजा की पत्नी कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ती है, मगर दिल्ली में डी. राजा कांग्रेस के नेताओं के साथ गलबहियां करते हैं। केरल में नूरा कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती। कांग्रेस और सीपीआई वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुकी हैं। यह लोग कुर्सी और सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंडी अलायंस की विचारधारा भ्रष्टाचार और वंशवाद है। सीपीआई के नेता भी अब भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट पर चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी ने कांग्रेस के झंडों को नीचे कर, मुस्लिम लीग के झंडे को ऊपर कर दिया था। भाजपा कहती है कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अपना देश अपनी माटी, मगर कांग्रेस सत्ता के लिए अपने झंडे को भी नीचे कर देती है और देश को टुकड़ों में बांटने वालों का झंडा उठा लेते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं, लगभग 1 लाख 16 हजार शक्ति केंद्रों के प्रमुख हैं और 6 लाख 80 हजार बूथ पर अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। विश्व के 60 से अधिक देशों के राजदूतों ने भाजपा कार्यालय आकर पार्टी को समझने की कोशिश की है और उन्होंने माना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 80 मिलियन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दोगुने हैं। आज 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के 1500 से अधिक चुनकर आए विधायक हैं, 200 से अधिक चुने गए मेयर हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के शासन में भारत विश्व में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाजपा सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए

43.35 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को एलडीएफ-यूडीएफ की सरकारों ने रोक रखा था, लेकिन आज विकास कार्यों की गति बढ़ी है। बीते 10 वर्षों में 15 हजार किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास हुआ है। 3.8 लाख किमी ग्रामीण सड़कों का विकास हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में डबल लेन सड़कों का विकास हुआ है। 2014 से पुर देश में 74 एयरपोर्ट थे जो आज बढ़कर 148 हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा का लाभ ले सके। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ा है, एक समय देश बुलेट प्रूफ जैकेट भी विश्व के अन्य देशों से खरीदता थे, लेकिन आज हम फाइटर जेट, टैंक और आधुनिक हथियार बनाकर विश्व के अन्य देशों को निर्यात भी कर रहा है। भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 3 करोड़ और घर बनाने का है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों ने भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ाया, देश विरोधी लोगों को ताकत प्रदान करने का कार्य किया और देश को आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास किए। केरल की एलडीएफ सरकार को-ऑपरेटिव और सोना घोटाला के भ्रष्टाचार में संलिप्त है। केरल की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी सरकार है। यूडीएफ भी इन मुद्दों को उठाने के बजाय राज्य सरकार की सहायता कर रही है। चोर-चोर मौसेरे भाई। 2026 में केरल में भी कमल खिलेगा और कोई भी भाजपा के सामने टिक नहीं पाएगा। ■

मोहन लाल बडौली बने हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जुलाई, 2024 को श्री मोहन लाल बडौली को भाजपा हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। अभी तक यह दायित्व मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के पास था। श्री बड़ौली वर्तमान में राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ■

भाजपा विकास एवं गरीब कल्याण के आधार पर आगे बढ़ी है, कांग्रेस केवल कट, कमीशन एवं करप्शन में ही लिप्त रहती है : अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 29 जून, 2024 को हरियाणा के पंचकुला में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 2014 की तुलना में इस लोकसभा चुनाव में 5 प्रतिशत अधिक मत प्राप्त किया है और पहले से ज्यादा सीटें जीती हैं। श्री शाह ने हरियाणा में भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि भाजपा भ्रष्टाचारमुक्त शासन लाने में सफल रही है। श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए भाजपा की आगामी चुनावों में जीत का विश्वास जताया और कांग्रेस पर भ्रांतियां फैलाने का आरोप लगाया।

श्री शाह ने बताया कि भिन्न-भिन्न प्रकार की भ्रांति फैलाकर कांग्रेस जनता में अपनी पराजय को विजय में बदलने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 की अपेक्षा में इस चुनाव में 5 प्रतिशत वोट ज्यादा मिले हैं। यूपीए के जितने भी दल हैं, उनको जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। मीडिया के कुछ समूह भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रचने वाले इस विजय को थोड़ा फीका बता रहे हैं। 60 के दशक के बाद जब विपक्ष भी नहीं होता था, उसके बाद पहली बार 6 दशक के बाद कोई एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी है और यह देश की जनता के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता था। हरियाणा में भी 2014 से भाजपा का मत प्रतिशत 5% तक बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा किसी के साथ न जाकर अकेले चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। भाजपा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हम हरियाणा की जनता का विश्वास फिर एक बार हासिल करेंगे और इसी विजय के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।

श्री शाह ने कहा कि प्रदेश में अब सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेन्द्र हुड्डा का सितारा दीपेन्द्र हुड्डा के नेतृत्व वाली तारा और सितारा की सरकार नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण के आधार पर आगे बढ़ी है। कांग्रेस सरकार केवल कट, कमीशन और करप्शन में ही लिप्त रहती है और इसके सहारे राजनीति करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार के तहत लाखों लोगों को पक्का घर मिला, शौचालयों का निर्माण किया गया, उज्ज्वला के कनेक्शन दिए, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाया और किसान निधि के माध्यम से किसानों तक सम्मान निधि पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत हरियाणा के 95 प्रतिशत गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाई, एक्सपोर्ट 68 हजार रुपए से बढ़कर 2 लाख 18 हजार रुपए पर पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय जो गरीबी उन्मूलन के लिए मानक मानी जाती है, उसे 1 लाख 48 हजार रुपए से बढ़ाकर 3 लाख 62 हजार रुपए करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हरियाणा में फसलों पर सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जाता है, वृद्धा सम्मान पेंशन योजना के तहत 3000 रुपए दिए जा रहे हैं, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन सबसे ज्यादा हरियाणा में दी जाती है और आशा वर्कर का भी सबसे ज्यादा भुगतान हमारे हरियाणा में ही होता है। भाजपा सरकार के तहत हिसार में इंटरनेशनल एविएशन हब बनाया, 1650 करोड़ रुपए की लागत से एम्स और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के 20 लाख लाभार्थी हैं, 83 हजार माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाया गया है, 30 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया, आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, 8 लाख शौचालय बनाए, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो अनाज दिया, 11 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिए और 96000 लोगों को घर देने काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किया है।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हरियाणा को दो तिहाई बहुमत से विजयी बनाने और भारतमाता का जयकारा लगाते हुए इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी। ■

नए प्रदेश प्रभारी एवं सह-प्रभारी नियुक्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 5 जुलाई, 2024 को विभिन्न प्रदेशों के लिए निम्नलिखित प्रदेश प्रभारी एवं सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं—

	प्रदेश	दायित्व	नाम
1	अंडमान एवं निकोबार	प्रभारी	श्री रघुनाथ कुलकर्णी
2	अरुणाचल प्रदेश	प्रभारी	श्री अशोक सिंघल, विधायक
3	बिहार	प्रभारी	श्री विनोद तावड़े
		सह प्रभारी	श्री दीपक प्रकाश, सांसद
4	छत्तीसगढ़	प्रभारी	श्री नितिन नवीन, विधायक
5	दादर नगर हवेली एवं दमन दीव	प्रभारी	श्री दुष्यन्त पटेल, विधायक
6	गोवा	प्रभारी	श्री आशीष सूद
7	हरियाणा	प्रभारी	डॉ. सतीश पूनिया
		सह प्रभारी	श्री सुरेंद्र सिंह नागर, सांसद
8	हिमाचल प्रदेश	प्रभारी	श्री श्रीकांत शर्मा, विधायक
		सह प्रभारी	श्री संजय टंडन
9	जम्मू-कश्मीर	प्रभारी	श्री तरुण चुघ
		सह प्रभारी	श्री आशीष सूद
10	झारखंड	प्रभारी	श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सांसद
11	कर्नाटक	प्रभारी	डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, सांसद
		सह प्रभारी	श्री सुधाकर रेड्डी
12	केरल	प्रभारी	श्री प्रकाश जावडेकर
		सह प्रभारी	श्रीमती अपराजिता सारंगी
13	लद्दाख	प्रभारी	श्री तरुण चुघ
14	मध्य प्रदेश	प्रभारी	डॉ. महेंद्र सिंह, एमएलसी
		सह प्रभारी	श्री सतीश उपाध्याय
15	मणिपुर	प्रभारी	डॉ. अजीत गोपछड़े, सांसद
16	मेघालय	प्रभारी	श्री अनिल एंटनी
17	मिजोरम	प्रभारी	श्री देवेश कुमार, एमएलसी
18	नागालैंड	प्रभारी	श्री अनिल एंटनी
19	ओडिशा	प्रभारी	श्री विजयपाल सिंह तोमर
		सह प्रभारी	सुश्री लता उसेंडी, विधायक
20	पुदुचेरी	प्रभारी	श्री निर्मल कुमार सुराणा
21	पंजाब	प्रभारी	श्री विजयभाई रूपानी
		सह प्रभारी	डॉ. नरिंदर सिंह
22	सिक्किम	प्रभारी	डॉ. दिलीप जयसवाल, एमएलसी
23	उत्तराखंड	प्रभारी	श्री दुष्यन्त कुमार गौतम
		सह प्रभारी	श्रीमती रेखा वर्मा
24	उत्तर पूर्व राज्य	समन्वयक	डॉ. संबित पात्रा, सांसद
		सह समन्वयक	श्री वी. मुरलीधरन

भारतीय जनसंघ ही क्यों?

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

भारतीय जनसंघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन (कानपुर, 29 दिसंबर, 1952) में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा दिए गए भाषण का प्रथम भाग

भारतीय जनसंघ के इस प्रथम वार्षिक अधिवेशन पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी वर्ष के लिए सर्वसम्मति से अपना प्रधान चुनकर आपने मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनसंघ का उदय केवल गतवर्ष के अक्टूबर मास की घटना है। उस समय देश के विभिन्न भागों से प्रतिनिधिगण दिल्ली में एकत्रित हुए थे और उन्होंने देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं तथा राष्ट्र की एकता व उत्थान में आने वाली बाधाओं पर विचार किया गया था। अपने जन्म के दो मास के ही अन्दर इस दल ने वयस्क मताधिकार पर आधारित साधारण चुनावों में भाग लेना निश्चित किया। साधनों के अभाव तथा तैयारी की कमी को देखते हुए यह एक साहस का कार्य था। इसका परिणाम असंदिग्ध रूप से निराशाजनक रहा। कांग्रेस ही उस समय सर्वाधिक संगठित राजनीतिक दल था और राज्यसत्ता भी उसी के हाथ में थी। ऐसी दशा में प्रतियोगी दलों की अधिकता तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों की बहुतायत के कारण उसे ही सफलता प्राप्त हुई, यद्यपि अनेक स्थानों पर बहुमत का निर्णय उसके विरुद्ध रहा। देश के अनेक स्थानों में सत्तारूढ़ दल पर चुनावों में, विशेषकर मतदान और परिणामों की घोषणा के बीच, अनीति और अनियमितता के भारी आक्षेप किए गए। इससे निर्वाचन नियम और विधियों में संशोधन की महती आवश्यकता प्रकट होती है। इतने पर भी हम जनसंघ का संदेश कितने ही प्रदेशों के कोने-कोने तक पहुंचाने में सफल हुए और सर्वसाधारण जनता का जो समर्थन हमें प्राप्त हुआ यह पर्याप्त उत्साहवर्धक था। यद्यपि अधिकांश स्थानों पर चुनाव का परिणाम हमारे प्रतिकूल गया, तो भी संसद और विधान सभाओं के लिए हमारे उम्मीदवारों को लगभग 70 लाख मत प्राप्त हुए। देश के विभिन्न भागों में यात्रा करते हुए मुझे सर्वसाधारण के मन पर यह अंकित करने का अवसर प्राप्त हुआ कि जनसंघ का जन्म केवल चुनाव लड़ने मात्र के लिए नहीं हुआ है, अपितु इसका उद्देश्य एक विशाल आधार पर अपना स्थायी संगठन करने का है जिससे यह भारत की

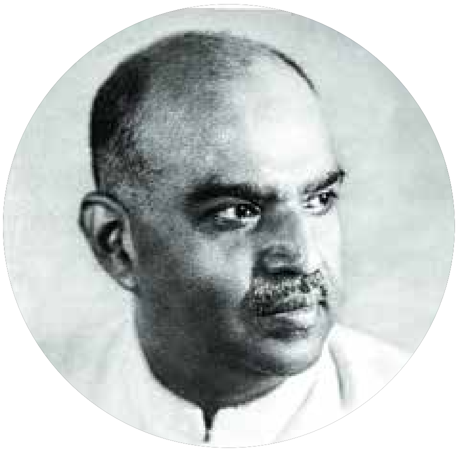

भावी उन्नति में सक्रिय हाथ बंटा सके। चुनावों के परिणाम से उत्पन्न स्वाभाविक निराशा के वातावरण का परिमार्जन करने के लिए हमें विशेष उद्योग करने पड़े। यह प्रयत्न सफल हुए हैं यह इसी बात से स्पष्ट है कि हमारे प्रथम वार्षिक अधिवेशन में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि एकत्र हैं। मुझे यह आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि हम अपनी शक्ति तथा साधनों को संगठित कर सकेंगे और हमारा यह दल शीघ्र ही जनता के हृदय में अपना स्थान बना लेगा।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण

जनसंघ की विचारधारा तथा कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण इसके जन्म के पश्चात् शीघ्र ही हो गया था। इनमें हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय, सभी मूलभूत समस्याओं पर विचार किया गया था। हमारे विचारधारा तथा कार्यक्रम पर होने वाली आलोचना तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं पर विचार करते हुए समय-समय पर हमने इनमें परिवर्तन भी किया है। जाति, मत अथवा संप्रदाय, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हमारा यह दल सभी के लिए खुला है। स्वतंत्र भारत में किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता को जाति, संप्रदाय अथवा मतादि के आधार पर खड़ा करना एक घातक भूल होगी। बिना किसी भी भेदभाव के भारतीय नागरिक के अधिकारों की समानता भारत के संविधान का आधार है जो कि प्रत्येक जनतंत्रवादी देश के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान द्वारा अपने संविधान को, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सन्निहित हैं, इस्लामी कानून तथा साम्प्रदायिक भेदभाव के आधार पर बनाने का प्रस्ताव उसकी प्रतिगामी प्रवृत्तियों को नग्न रूप में प्रस्तुत करता है।

अनेक शताब्दियों से भारत विभिन्न मत-मतान्तरों को मानने वाले लोगों की मातृभूमि रहा है। उनके व्यक्तिगत आचारधर्म की, विशेषकर उपासना और आधारभूत सामाजिक कर्तव्यों संबंधी, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता निर्विवाद है। नागरिक अधिकार तथा कर्तव्यों में सब समान हैं। स्वस्थ और प्रगतिशील सहयोग का भाव उत्पन्न करते हुए हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलें। यह पारस्परिक सहिष्णुता, सद्भाव और अवसर की सच्ची समानता से ही संभव होगा। हमारे दल का द्वार बिना किसी प्रकार के जाति अथवा मत संबंधी भेदभाव के उन सभी के लिए खुला है जो हमारे कार्यक्रम तथा विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यदि

कुछ वर्ग हमारे साथ आना नहीं चाहते तो भी हम सर्वसाधारण जनता की सद्भावना तथा सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यह भी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए उसने बनावटी हिन्दू-मुस्लिम एकता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। फलस्वरूप मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को राष्ट्र के हित में घातक समझौते पर समझौते स्वीकार करने पड़े। अन्त में जिन विघटनकारी वृत्तियों को कांग्रेस ने तुष्टीकरण के द्वारा जीतना चाहा था, उन्होंने कल्पनातीत भयंकर रूप धारण किया और उसका परिणाम देश का विभाजन हुआ। उपासना पद्धति को राष्ट्रीयता का आधार बनाने, या मतपरिवर्तित व्यक्तियों अथवा उनके वंशजों द्वारा मजहब के आधार पर देश का सफलतापूर्वक विभाजन कराने की घटना और कहीं नहीं सुनी। जनसंघ का मत है कि विभाजन से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, न भारत में, न पाकिस्तान में। इससे देश प्रत्येक प्रकार से दुर्बल हुआ है। यही नहीं, जिस समस्या को हल करने के लिए विभाजन स्वीकार किया गया था वही और अधिक भयंकर हो गई है और एक शान्तिपूर्ण हल निकल नहीं पा रहा है। अतः हमारे सामने अखंड भारत कोई अवास्तविक स्वप्न अथवा नारा मात्र नहीं है। यह हमारी श्रद्धा का विषय है और वह लक्ष्य है जो जनता के सहयोग और समझ से प्राप्त होगा ही।

सुव्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था

हमारा यह विश्वास है कि भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की सर्वोच्च परम्परा के अनुरूप जनता के चारित्रिक तथा मानसिक विकास एवं भारत की पूर्ण आर्थिक उन्नति, इन दोनों के समन्वय पर ही देश की भावी उन्नति आधारित है। आर्थिक स्वातन्त्र्य के बिना जो राजनीतिक स्वातन्त्र्य हमने प्राप्त किया है वह निरर्थक होगा। यह एक अत्यन्त दुःखदायी स्थिति है कि भारत जैसा विशाल देश अपने प्रायः असीम प्राकृतिक साधनों तथा कच्चे माल के होते हुए दारिद्र्य, रोग, अविद्या तथा पतन के गर्त में पड़ा रहे। हमारे दल का यह विश्वास है कि देश को हिंसात्मक अशान्ति तथा विग्रह में बिना झोंके हुए भी हमारे लिए यह सम्भव है कि जनता के आर्थिक शोषण और मूक वेदनाओं का अन्त कर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकें। अतः भूमि और कृषि, छोटे-बड़े और बीच के उद्योगों का संगठित विकास, तथा उत्पादन वृद्धि और उचित वितरण, आदि विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में जनसंघ का दृष्टिकोण यथार्थवादी और प्रगतिशील है। अवसर की सच्ची समानता तब तक सम्भव नहीं जब तक कि जनता के निर्धन तथा पिछड़े हुए वर्गों को उचित शैक्षणिक एवं आर्थिक सुविधायें प्राप्त न हों ताकि उनकी वे भारी कमियां दूर हो सकें जिनसे वे आज त्रस्त हैं।

आध्यात्मिक पुनर्जागरण

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि केवल आर्थिक विकास न तो मनुष्य के अन्तःकरण को पूर्ण शान्ति दे सकता है और न उसके दृष्टि की पूर्ण प्राप्ति में सहायक होता है। भारत ने उन मनः प्रवृत्तियों को जन्म दिया है जो उन्नति और प्रगति का दावा करने वाले अनेक देशों से भिन्न उसकी अपनी विशेषता है। जीवन में सादगी, सेवा और त्याग का भाव, संतोष तथा निःस्वार्थ, निःस्पृहता का दृष्टिकोण, बन्धुत्व एवं पावित्र्य का भाव, शक्ति और विनम्रता, सहिष्णुता तथा ऐक्य का योग अनादि काल से सुसंस्कृत मानवीय आचार का आदर्श रहा है। हमारा देश अच्छाई तथा बुराई का एक विचित्र सम्मिश्रण है। मानव जीवन के गूढ़तम रहस्यों का उद्‌घाटन करने वाले सत्य को यहां अति सरल ढंग से उदार हृदय होकर प्रकट किया गया है। इन सत्यों को आचरण में प्रकट करने वाले इक्के-दुक्के उदाहरण अवश्य मिलते हैं, किन्तु इन महान् शिक्षाओं के साथ अधिकांश लोगों के आचरण की संगति कठिनाई अवश्य पहुंचाएगा। प्रश्न केवल यह है कि यदि हम इसी गति से चलते रहे और दशा को अधिकाधिक बिगड़ने दिया तो क्या पीड़ित जनता का धैर्य अटूट बना रहेगा और क्या वे सदा ही इसी प्रकार चुपचाप सहन करते रहेंगे? यदि सरकार द्वारा अपने कर्तव्यपालन में असफल होने पर जनक्षोभ उसके विरोध में एक बार भी भड़क उठा तो हमें बहुत अधिक धन-जन की हानि उठानी पड़ेगी, जो शायद अन्यथा बचाई जा सकती है।

इस योजना के इसी रूप में भी पूर्ण होने के सम्बन्ध में कुछ चेतावनी के शब्द कह देना आवश्यक है। इसको क्रियान्वित करने के लिए बनाई गयी व्यवस्था पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यह आवश्यक है कि इस उद्देश्य के लिए ऐसे ही लोगों का चुनाव हो जो पूर्ण योग्य हों और जिनमें हृदय की विशालता तथा सेवा का भाव हो। इन गुणों के कारण वे केवल वेतन प्राप्त कर्मचारी न होकर, योजनाबद्ध राष्ट्रीय विकास के नवीन युग को लाने वाले निमित्त होंगे। अतः उनका चुनाव पक्षपात, संरक्षकता अथवा दलगत भावनाओं के अनुसार कदापि नहीं होना चाहिए। किसी भी संगठित योजना की सफलता के लिए सार्वजनीन सहयोग का सच्चा वातावरण आवश्यक है। इतने गाने-बाजे से स्थापित किए गये 'भारत सेवक समाज' की प्रगति भी एक दल-निरपेक्ष संगठन के रूप में नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त आज के सत्ताधारियों द्वारा योजना का दुरुपयोग अपने दलीय स्वार्थों के लिए किए जाने की भी बहुत गुंजाइश तथा संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो इससे न केवल नितान्त आवश्यक सार्वजनीन सहयोग तथा उत्साह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, वरन् इस योजना को चलाने की सारी व्यवस्था ही दूषित हो जाएगी और इस प्रकार इसकी सफलता के सभी अवसर नष्ट हो जायेंगे। योजना के अनुसार राज्य के द्वारा उठाये गये किसी भी निर्णय, कार्य के ऊपर आदि से अन्त तक कठोर देखरेख रखना आवश्यक होगा। राज्य के द्वारा उठाये गये कुछ कार्यों में अच्छी सफलता मिली है, उदाहरणार्थ सिन्दरी का खाद का कारखाना, चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी, दामोदर घाटी कारपोरेशन आदि। इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि सामान की बरबादी और अन्य अनियमितता तथा भूलें जो पहले हो चुकी हैं, फिर भविष्य में भी दोहराई जायें।

क्रमशः

सुशासन के प्रतीक: छत्रपति शिवाजी महाराज

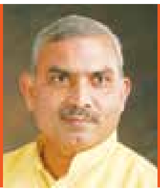

शिवप्रकाश

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित 'धन्यवाद भारत कार्यक्रम' के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करते हुए कहा, "कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण की 350वीं वर्षगांठ मनायेगा, उनका जीवन ध्येय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है।" छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत् 1731 को रायगढ़ में हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 6 जून, 1674 की वह तिथि थी। पुर्तगाली एवं ब्रिटिशों सहित अनेक विदेशी लेखकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना विश्व के महानतम सेनापति नेपोलियन, सीजर, सिकन्दर के साथ करते हुए उनकी वीरता, साहस, प्रशासनिक कुशलता एवं युद्ध शैली की प्रशंसा की है।

16 फरवरी, 1630 ईस्वी शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म शाहजी भोंसले एवं माता जीजाबाई के परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय परिस्थिति कैसी थी इसका वर्णन समर्थ गुरु रामदास महाराज ने अपने 12 वर्ष के भारत भ्रमण के पश्चात् इस प्रकार किया "या भूमंडलाचे ढायी, धर्मरक्षा ऐसा नाही" इस समय इस भूमंडल पर धर्मरक्षक कोई नहीं है। सम्पूर्ण देश में कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं है, सामान्य जनता मुगलों के अत्याचार से कराह रही है, किसी भी नदी का जल पवित्र नहीं है जिससे अभिषेक किया जा सके। इस विकट परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रणकौशल एवं बुद्धि-कौशल से स्वराज की स्थापना की। उनके कुशल प्रशासन को देखने के बाद

> **शिवाजी महाराज ने सहयाद्रि में निवास करने वाले सामान्य गरीब, किसान, युवकों में स्वराज की प्रेरणा जगायी। समाज के सामान्य वर्ग से निकले इन्हीं योद्धाओं ने अपने जीवन की बाजी लगाकर स्वराज स्थापना का श्रेष्ठतम कार्य किया**

पुनः स्वयं समर्थ रामदास महाराज ने कहा कि "आचारशील, विचारशील, न्यायशील, धर्मशील, सर्वज्ञ सुशील जाणता राजा" (जाणता अर्थात् सदैव जागरूक)।

किसी भी कार्य की सफलता का आधार नेतृत्वकर्ता के सहयोगी कैसे है, इस पर निर्भर करता है। शिवाजी महाराज ने सहयाद्रि में निवास करने वाले सामान्य गरीब, किसान, युवकों में स्वराज की प्रेरणा जगायी। समाज के सामान्य वर्ग से निकले इन्हीं योद्धाओं ने अपने जीवन की बाजी लगाकर स्वराज स्थापना का श्रेष्ठतम कार्य किया। औरंगजेब अपनी सेना के एक-एक सेनापति से तुलना करते हुए शिवाजी महाराज के सेनापतियों की विशेषता का वर्णन करते हुए कहता है, "वे झुकते नहीं, रुकते नहीं, थकते नहीं और बिकते भी नहीं।"

छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन लोक कल्याण एवं पारदर्शिता से युक्त था। अपने वित्त प्रबंधन को लेकर वे सदैव सजग थे। अपने मंत्रालयों की समीक्षा करते समय उन्होंने अपने लेखपाल से पूछ लिया कि कल तक का हिसाब दैनिंदनी में चढ़ा अथवा नहीं, नकारात्मक उत्तर होने पर लापरवाही के लिए कठोर दंड भी दिया। लगान के उचित संग्रह में लापरवाही पर देश कुलकर्णी आपाजी से जुर्माना भी लिया एवं पद मुक्त भी किया। भ्रष्टाचार विहीन शासन छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन का वैशिष्ट्य था। भ्रष्टाचार युक्त शासन के लिए उन्होंने रिश्वत लेने पर अपने सौतेले मामा मोहिते को भी कारागार में डाल दिया था। 13 मई 1671 के अपने पत्र में वे लिखते है कि अगर आप जनता को तकलीफ देंगे, कार्य सम्पादन में रिश्वत मागेंगे, तो जनता को लगेगा कि इससे तो मुगलों का शासन ही अच्छा था।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज संचालन के लिए अष्ट प्रधान शासन

शेष पृष्ठ ३२ पर...

गुरु पूर्णिमा (21 जुलाई) पर विशेष

भारत में सबसे पवित्र और सर्वोच्च है 'गुरु-शिष्य संबंध'

गुरु पूर्णिमा का है ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्त्व

तरुण चुघ

भारत एक सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर चलने वाला देश है। संबंधों को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। इसी कड़ी में गुरु-शिष्य संबंध को सबसे पवित्र और सर्वोच्च माना गया है। कहा भी गया है– "गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।" इसलिए सभी आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को सम्मान देने के लिए समर्पित त्योहार के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व है। यह एक अंतरराष्ट्रीय त्योहार है, जिसे भारत के अलावा नेपाल, भूटान समेत कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास की जयंती भी है।

गुरु शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है, जो 'गु' और 'रु' से लिया गया है। यहां 'गु' का अर्थ अंधकार या अज्ञान है और 'रु' का अर्थ दूर करने वाला होता है। इसलिए गुरु को अंधकार या अज्ञान का नाश करने वाला कहा जाता है।

गुरु पूर्णिमा का उत्सव आध्यात्मिक एवं सामाजिक तरीके से मनाया जाता है। इसमें गुरु के सम्मान में अनुष्ठानिक कार्यक्रम होता है। धार्मिक महत्त्व होने के अलावा इस त्योहार का भारतीय शिक्षाविदों और विद्वानों के लिए भी महत्त्व रखता है। भारत में इस दिन अपने शिक्षकों को धन्यवाद देने और उन्हें याद करके सम्मान देते हैं।

बौद्ध परंपरा के अनुसार यह त्योहार बौद्धों द्वारा भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन ऋषि व्यास के सम्मान में भी मनाया जाता है, जिन्हें प्राचीन हिंदू परंपराओं में सबसे महान गुरुओं में से एक और गुरु-शिष्य परंपरा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। जैन परंपराओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा को त्रीनोक गुहा पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, जिसमें अपने त्रीनोक गुहाओं और शिक्षकों को विशेष सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा का त्योहार हिन्दुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। सिख धर्म में भी गुरु को सर्वस्व माना गया है। भारतीय संस्कृति में भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है। गुरु के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। माता-पिता हमें संस्कार देते हैं तो दूसरी तरफ गुरु हमें ज्ञान देता है।

> **गुरु पूर्णिमा के त्योहार का नाम सूर्य के प्रकाश से पड़ा, जो चंद्रमा को चमकाता है, अर्थात एक छात्र केवल तभी चमक सकता है, जब उसे गुरु का प्रकाश मिले**

गुरु का ज्ञान और शिक्षा ही जीवन का आधार है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार आषाढ़ माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को है।

एक छात्र जो सीख और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गुरु कैसा है? इस प्रकार गुरु पूर्णिमा के त्योहार का नाम सूर्य के प्रकाश से पड़ा, जो चंद्रमा को चमकाता है, अर्थात् एक छात्र केवल तभी चमक सकता है, जब उसे गुरु का प्रकाश मिले।

महाभारत के रचयिता वेद व्यास को सम्मानित करने के लिए इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन जन्म लेने वाले ऋषि वेद व्यास को गुरु-शिष्य परंपरा का अग्रणी भी माना जाता है। अक्सर लोग अपने गुरुओं के सम्मान और स्मरण के लिए अपने घरों में भी गुरु की पूजा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला गुरु उसके माता, पिता या अभिभावक होते हैं, जो उन्हें सबसे पहले उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें जीवन के सच्चे मूल्य सिखाते हैं और तमाम अवगुणों से भी दूर रखते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्योहार पर हिंदू धर्म के लोग भगवान शिव की पूजा भी पूजा करते है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव को आदिगुरु माना जाता है, जिन्होंने अपने सात अनुयायियों को योग का ज्ञान दिया और इस तरह उन्हें सबसे महान गुरु माना जाता है। बौद्ध धर्म मानने वाले लोग इस त्योहार को भगवान बुद्ध को सम्मान देने के लिए मनाते हैं, जिन्होंने धर्म की बौद्ध नींव रखी। बौद्धों का मानना है कि इस पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ शहर में अपना पहला उपदेश दिया था। तभी से उनकी पूजा के लिए गुरु पूर्णिमा के पर्व को चुना गया है। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर हो। समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम स्थान दिया गया है। गुरुओं की इस भूमिका को सरल और गूढ़ रूप में संत कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से दर्शाते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है कि–

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पांव।
बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए।।

अर्थात्, गुरु और गोविंद दोने एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए? गुरु को या गोविंद को? फिर अगली पंक्ति में उसका जवाब देते हुए संत कबीर दास जी लिखते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनसे प्राप्त ज्ञान के माध्यम से

ही मनुष्य को गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

कबीरदास ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाते हुए अपने दोहे में लिखा है कि–

गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोष।
गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष।।

इस दोहे में कबीरदास ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना किसी भी प्रकार के ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अधंकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करते हैं। उनके योगदान की चर्चा सार्वजनिक तौर पर करते हुए देश को यह संदेश देते हैं कि गुरु के प्रति सम्मान भाव ही भारत का संस्कार है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

पृष्ठ 30 का शेष...

प्रणाली की व्यवस्था दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जहां एक दूरदर्शी योद्धा थे, वहीं वह एक कुशल प्रशासक भी थे। स्वदेशी जलपोत निर्माण के लिए मुंबई के पास कल्याण एवं भिवंडी में उनके द्वारा स्थापित जलपोत निर्माण करवाना, व्यापार एवं सुरक्षा के प्रति उनकी दृष्टि की ओर इंगित करता है। अंग्रेजों से तोप निर्माण की तकनीक न मिलने पर उन्होंने फ्रांस के सहयोग से पुरन्दर किले पर तोपखाना स्थापित कराया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का यह मन्त्र वर्तमान की सरकार का मन्त्र भी बना है। भूमि का मापन, पैदावार का मूल्यांकन, आपदा में होने वाली हानि के मूल्यांकन की व्यवस्था शिवाजी महाराज ने उस समय की थी। सिंचाई के लिए बांध, तालाबों, कुएं, बावड़ी एवं जलाशयों का निर्माण उनकी दूरदर्शिता को प्रकट करते है। स्वस्थ भूमि, स्वस्थ उत्पाद, स्वस्थ पर्यावरण के लिए फसलों में विविधता, फलदार वृक्षों को लगवाना उनकी कृषि एवं पर्यावरण के प्रति दृष्टि को प्रकट करते है।

महिलाओं के प्रति उनके ह्रदय में सम्मान एवं महिलाओं के प्रति कुदृष्टि डालने पर कठोर दंड उनके शासन की व्यवस्था थी। मुस्लिम महिला गोहरबानू के प्रति उनके उदगार काश मेरी मां भी इतनी सुन्दर होती, सखोजी गायकवाड़ को दंड उनकी न्यायप्रियता को प्रकट करते है। स्वराज के हित को प्रथम रखते हुए उन्होंने व्यापारिक सम्बन्ध सभी से रखे थे। व्यापार के लिए मध्य एशिया के देशों तक उन्होंने सम्बन्ध बनाये थे। उसमें मस्कट के इमाम भी प्रमुख थे। उन्होंने अन्धविश्वास एवं कुरीतियों को तोड़ते हुए वैज्ञानिक दृष्टि को अपने राज्य संचालन का आधार बनाया। उनके शासन में वृद्ध, बीमार एवं बच्चों को छोड़कर अन्य किसी के लिए भी मुफ्त सुविधा की व्यवस्था नहीं थी।

छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली में स्वभाषा एवं स्व-संस्कृति को विशेष महत्त्व था। गुलामी के प्रतीकों को हटाकर स्वाभिमानी समाज जागृत करने के लिए उन्होंने किलों के नामों को नामांतरण भी किया। उर्दू और फारसी के शब्द बदलकर स्वराज संचालन के लिए 1400 हिन्दी शब्दों का कोश भी बनाया था।

छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था, शत्रु को पहचानने की उनकी अचूक दृष्टि उनको शेष भारतीय राजा-महाराजाओं से अलग करती है। उत्तर भारत की मुग़ल शक्ति एवं दक्षिण की आदिलशाही, कुतुबशाही के भेद का उन्होंने उचित उपयोग किया था। अंग्रेज व्यापारी स्वभाव के हैं, उन्होंने इसको अच्छे से पहचानकर उसी दृष्टि से उनके साथ व्यवहार भी किया था। शत्रु की कमजोरी उनके साथ 'जैसे को तैसा व्यवहार' (शठे शाठयम् समाचरेत) शाइस्ताखान, अफजलखान एवं औरंगजेब से युद्ध करते समय उन्होंने अपनाया था। व्यापार एवं सुरक्षा के लिए नौसेना के महत्त्व को पहचान कर सिंधुदुर्ग सहित समुंद्र किनारे अनेक दुर्गों की स्थापना उन्होंने की थी। अपने धर्म से विमुख हुए लोगों को अपने धर्म में पुनः वापसी भी उन्होंने करायी थी।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल हिन्दवी साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि सम्पूर्ण समाज में स्वराज, स्वधर्म के प्रति समर्पण की भावना भी जागृत की। देश भर में स्वराज की रक्षा के लिए संघर्षरत समस्त राजा-महाराजाओं के प्रेरणा पुंज भी वह बने। बुंदेलखंड के महराजा छत्रसाल, असम के लाचिद बड़फूकन उन्हीं से प्रेरणा लेकर संघर्ष कर रहे थे। विजय प्राप्ति पर अहोम राजाओं ने कहा कि हमारी प्रेरणा का केंद्र शिवाजी है।

अपनी माता की मृत्यु के समय भी बिना अवकाश लिए वे राज्य का सूत्र संचालन करते रहे और न ही कोई शासकीय अवकाश घोषित किया। स्वराज संस्थापन के लिए निःस्वार्थ भाव से कार्य करना ही उनकी प्रेरणा थी। स्वराज स्थापन यह 'श्री' का कार्य है यह मानकर उन्होंने सम्पूर्ण जीवनभर संघर्ष किया। अपने सहयोगियों में भी उन्होंने यही भाव कूट-कूट कर भरा था। सहयोगियों से वे कहते थे कि हमारे कार्य की दिशा ठीक है, यह पवित्र कार्य है। हमारा कार्य पवित्र होने के करण पवित्र अदृश्य शक्तियां हमारा सहयोग करेंगी। मां तुलजा भवानी एवं परमेश्वर पर यह आस्था ही उनके संघर्ष की प्रेरणा थी। निमित्तता के इसी निःस्वार्थ भाव के कारण उन्होंने एक कागज पर लिखकर अपना राज्य अपने प्रेरणास्रोत समर्थ रामदास स्वामी महाराज की झोली में डाल दिया था।

हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना के इस पुनीत अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन आदर्श से प्रेरणा लेकर अपने देश को आत्मनिर्भर, आर्थिक सम्पन्न, सुरक्षित एवं सांस्कृतिक मूल्यों से संरक्षित कर विश्व वन्दनीय भारत बनाएं। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह-महामंत्री {संगठन} हैं)

18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र के आरंभ होने से पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित किया

अपने तीसरे कार्यकाल में हम तीन गुना अधिक श्रम करेंगे और तीन गुना अधिक परिणाम अर्जित करेंगे: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून को 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र के आरंभ होने से पहले मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य का आरंभ करते हुए कहा कि आज का दिन संसदीय लोकतंत्र के लिए गौरव का दिन है, गर्व करने का दिन है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार शपथ ग्रहण समारोह नई संसद में होगा। श्री मोदी ने कहा, "इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को बधाई देता हूं।"

स्वतंत्रता के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर मिला

प्रधानमंत्री ने इस संसद के गठन को भारत के आम आदमी के संकल्पों को पूरा करने का माध्यम बताते हुए कहा कि यह नए उत्साह के साथ नई गति और ऊंचाई हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने के लिए आज 18वीं लोकसभा शुरू हो रही है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव का भव्य आयोजन 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, "चुनावी प्रक्रिया में 65 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया।" उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर मिला है। यह अवसर 60 वर्षों के बाद आया है।

श्री मोदी ने तीसरी बार सरकार चुनने के लिए नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सरकार की नीयत, नीतियों और लोगों के प्रति समर्पण पर मुहर लगाता है। उन्होंने बल देकर कहा, "पिछले 10 वर्षों में हमने एक परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वसम्मति अत्यधिक आवश्यक है।" उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि 140 करोड़ नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वसम्मति हासिल की जाए और सभी को साथ लेकर मां भारती की सेवा की जाए।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा

श्री मोदी ने कल यानी 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि भारत की नई पीढ़ी उस दिन को कभी नहीं भूलेगी, जब लोकतंत्र को कुचलकर भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था और देश को जेलखाने में बदल दिया गया था। श्री मोदी ने नागरिकों से भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया, ताकि ऐसी घटना फिर कभी न हो।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार की जिम्मेदारी तीन गुना बढ़ गई है, क्योंकि लोगों ने तीसरी बार सरकार चुनी है। उन्होंने नागरिकों को विश्वास दिलाया कि सरकार पहले से तीन गुना अधिक श्रम करेगी और तीन गुना बेहतर परिणाम भी लाएगी। श्री मोदी ने सभी सांसदों की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि वे सामूहिक रूप से 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करें और लोगों का भरोसा मजबूत करें। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ नागरिकों का निर्धनता से बाहर आना एक नया विश्वास पैदा करता है कि भारत सफल हो सकता है और अतिशीघ्र निर्धनता से मुक्ति पा सकता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक कड़ी मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। हमें उन्हें अधिकतम अवसर प्रदान करने चाहिए।" ■

ओम बिरला 18वीं लोकसभा के चुने गए अध्यक्ष

पिछली लोकसभा में बिरलाजी का नेतृत्व हमारे संसदीय इतिहास का स्वर्णिम कालः प्रधानमंत्री

श्री ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 जून को लोकसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने श्री बिरला के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद संभालने का स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष को सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं। अमृत काल के दौरान श्री बिरला के दूसरी बार कार्यभार संभालने के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि श्री बिरला को उनके पिछले पांच साल के अनुभव और उनके साथ संसद सदस्यों के अनुभव से इस महत्त्वपूर्ण समय में सदन का मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के विनम्र तथा नम्र व्यक्तित्व और उनकी विजयी मुस्कान से उन्हें सदन का संचालन करने में मदद मिलती है

प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि लोकसभा के दोबारा चुने गए अध्यक्ष नई सफलता हासिल करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले श्री बलराम जाखड़ लगातार पांच वर्षों के बाद फिर से इस पद पर आसीन होने वाले पहले अध्यक्ष थे और आज श्री ओम बिरला हैं, जिन्हें 17वीं लोकसभा के सफल समापन के बाद 18वीं लोकसभा का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने बीच में 20 साल की अवधि की प्रवृत्ति की ओर भी इशारा किया जिस दौरान लोकसभा का अध्यक्ष चुने गए लोग या तो चुनाव नहीं लड़े या अध्यक्षीय कार्यकाल के बाद चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन यह श्री ओम बिरला हैं जिन्होंने चुनाव में फिर से विजयी होने के बाद अध्यक्ष के रूप में वापसी करके इतिहास रचा है।

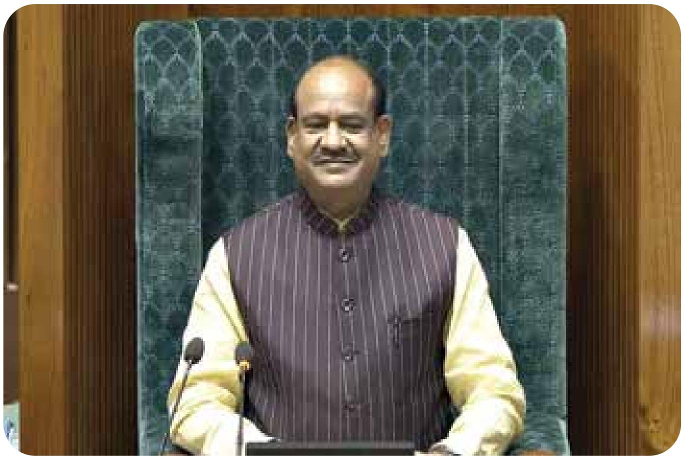

17वीं लोकसभा के दौरान लिए गए अनेक परिवर्तनकारी फैसले

पिछली लोकसभा के दौरान श्री बिरला के नेतृत्व को याद करते हुए श्री मोदी ने उस अवधि को हमारे संसदीय इतिहास का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने 17वीं लोकसभा के दौरान लिए गए परिवर्तनकारी फैसलों को याद करते हुए अध्यक्ष के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक जैसे अनेक ऐतिहासिक अधिनियमों का उल्लेख किया, जिन्हें श्री ओम बिरला की अध्यक्षता में पारित किया गया।

श्री मोदी ने वर्तमान अध्यक्ष की अध्यक्षता में नए संसद भवन के उद्घाटन को याद किया और लोकतांत्रिक पद्धतियों की नींव को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों की भी सराहना की। उन्होंने सदन में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष श्री बिरला द्वारा शुरू की गई पेपरलेस वर्कफ़्लो और व्यवस्थित ब्रीफिंग प्रक्रिया की भी सराहना की।

श्री मोदी ने जी-20 देशों के विधायी निकायों के अध्यक्षों के बेहद सफल पी-20 सम्मेलन के लिए भी अध्यक्ष की सराहना की, जिसमें बड़ी संख्या में देशों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा की रिकॉर्ड उत्पादकता का उल्लेख किया जो 97 प्रतिशत रही। श्री मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान सदन के सदस्यों के प्रति अध्यक्ष के व्यक्तिगत संबंध और चिंता का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने श्री बिरला की इस बात के लिए भी सराहना की कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भी सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं होने दिया। उस दौरान संसद की उत्पादकता 170 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

श्री मोदी ने सदन की गरिमा को बनाए रखने में अध्यक्ष द्वारा दिखाए गए संतुलन की सराहना की जिस दौरान कई कठोर निर्णय लेना भी शामिल था। उन्होंने परंपराओं को बनाए रखते हुए सदन के मूल्यों को बनाए रखने का विकल्प चुनने के लिए अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। ■

3 नए आपराधिक कानून 01 जुलाई से हुए लागू

नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशभर में 01 जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला और पीड़ित-केन्द्रित बताया। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक जुलाई को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानूनों को हर पहलू पर 4 वर्षों तक विस्तार से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करके लाया गया है और आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशभर में एक जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला और पीड़ित-केन्द्रित बताया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनता के मन में इन कानूनों के बारे में भ्रम पैदा करना है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को हर पहलू पर 4 वर्षों तक विस्तार से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करके लाया गया है और आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली आज पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और यह तीन नए कानून आज से देश के हर पुलिस थाने में लागू हो जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों के आधार में दंड की जगह न्याय, देरी की जगह त्वरित ट्रायल और त्वरित न्याय को रखा गया है। इसके साथ ही पहले के कानूनों में सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, लेकिन इन नए कानूनों में अब पीड़ितों और शिकायतकर्ता के अधिकारों की भी रक्षा करने का प्रावधान है।

श्री अमित शाह ने कहा कि कल मध्यरात्रि से देशभर में प्रभाव में आए इन तीन नए कानूनों के लागू होने से हमारे देश की पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली में भारतीय आत्मा दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे देश के नागरिकों को कई प्रकार के फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में अंग्रेजों के समय विवाद में रहे कई प्रावधानों को हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों में भारतीय संविधान की स्पिरिट के अनुरूप धाराओं ओर अध्यायों की प्राथमिकता तय की गई है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई है। श्री शाह ने कहा कि बच्चों व महिलाओं के प्रति अपराध पर नया अध्याय, जिसमें 35 धाराएं और 13 प्रावधान हैं, जोड़कर इसे और भी संवेदनशील बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मॉब

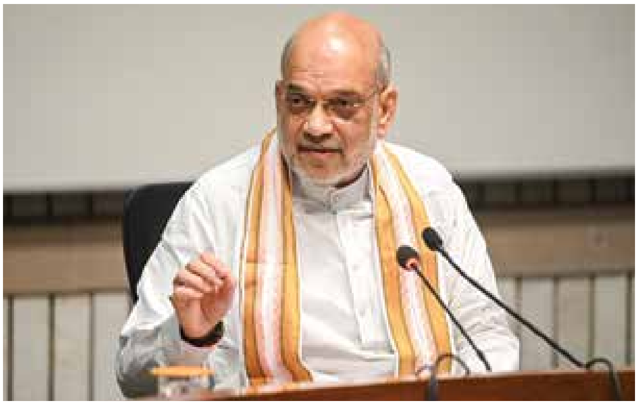

लिंचिंग के अपराध के लिए पहले के कानून में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इन कानूनों में पहली बार बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित और इसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह का कानून जड़ से समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून में देशविरोधी गतिविधियों के लिए नई धारा जोड़ी गई है, जिसके तहत भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने वालों को कड़ी सज़ा का प्रावधान है।

श्री अमित शाह ने कहा कि तीनों नए कानून पूरी तरह से लागू होने के बाद सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेंगे। इन कानूनों के देशभर में पूरी तरह लागू होने के बाद भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिकतम न्याय प्रणाली बन जाएगी। उन्होंने कहा कि तीनों नए कानूनों में तकनीक को न केवल अपनाया गया है, बल्कि इस तरह का प्रावधान भी किया गया है कि अगले 50 सालों में आने वाली सभी तकनीकें इसमें समाहित हो सके। उन्होंने कहा कि देशभर के 99.9 प्रतिशत पुलिस थाने कंप्यूटराइज़्ड हो चुके हैं, ई-रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी 2019 से शुरू हो गई थी, जीरो-FIR, E-FIR और चार्जशीट सभी डिजिटल होंगे। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समय-सीमा भी तय की गई है, पूरी तरह लागू होने के बाद तारीख पर तारीख से निजात मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मामले में FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल सकेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में 7 साल या उससे

अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है, इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष-सिद्धि दर को 90% तक ले जाने में सहायक होगा। श्री शाह ने कहा कि फॉरेन्सिक विजिट को अनिवार्य बनाने में हमने दूरदर्शिता के साथ काम कर 2020 में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बना दी थी। श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी साक्ष्य के संबंध में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अब सर्वर लॉग्स, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉयस मैसेजेज़ की व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि तीनों कानून देश की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और केस भी उन्हीं भाषाओं में चलेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय, हर राज्य के गृह विभाग और न्याय मंत्रालय ने बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में आज के समय के हिसाब से धाराएं जोड़ी गयी हैं और कई ऐसी धाराएं हटाई भी गयी हैं, जिससे देशवासियों को परेशानी थी। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों पर लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने का लक्ष्य था, हालांकि कई इंस्टीट्यूशंस को अधिकृत किया करके 23 हजार से अधिक मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ज्यूडिशरी में 21,000 सबोर्डिनेट ज्यूडिशरी की ट्रेनिंग हो चुकी है, साथ ही 20 हजार पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को ट्रेंड किया गया है। श्री शाह ने बताया कि इन कानूनों पर लोकसभा में कुल 9 घंटे 29 मिनट चर्चा हुई जिसमें 34 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि राज्यसभा में 6 घंटे 17 मिनट चर्चा हुई और उसमें 40 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है, इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष-सिद्धि दर को 90% तक ले जाने में सहायक होगा। श्री शाह ने कहा कि फॉरेन्सिक विजिट को अनिवार्य बनाने में हमने दूरदर्शिता के साथ काम कर 2020 में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बना दी थी

श्री अमित शाह ने कहा कि 2020 में उन्होंने सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह सचिव ने देश के सभी आईपीएस अधिकारियों और ज़िलाधिकारियों से इस संबंध में सुझाव मांगे थे। श्री शाह ने बताया कि उन्होंने स्वयं 158 बार इन कानूनों की समीक्षा बैठक की। इसके बाद इन कानूनों को गृह मंत्रालय की समिति के पास भेजा गया जहां ढाई-तीन महीने इन पर गहन चर्चा हुई और सभी दलों के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। श्री शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक सुझावों को छोड़कर हर सुझाव को समाहित कर कुल 93 बदलावों के साथ इस बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और फिर इसे संसद में रखा गया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े सुधार को पॉलिटिकल कलर देना ठीक नहीं है और यह कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान की स्प्रिट के अनुसार समय पर न्याय और आत्मसम्मान दिलाने की एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि भारत के आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है।

प्रेस वार्ता के दौरान 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि नए कानूनों में रिमांड का समय बढ़ गया है, पर सच यह है कि नए कानूनों के तहत भी रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही है। इस बारे में भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इन कानूनों में 60 दिनों के अंदर कुल 15 दिनों की रिमांड का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि 15 दिन की रिमांड की लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है और इस बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है। ■

राहुल गांधी के नफरत भरे भाषण के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजयुमो का विरोध प्रदर्शन

भारतीय जनता युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं ने 03 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के खिलाफ था। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी

से बिना शर्त माफी मांगने की मांग करते हुए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, सांसद श्री मनोज तिवारी, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ■

योग केवल एक विधा ही नहीं अपितु एक विज्ञान भी है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून को जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व करते हुए योग सत्र में भाग लिया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग और साधना की भूमि जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर में योग से उत्पन्न वातावरण, ऊर्जा और अनुभव को महसूस किया जा सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में योगाभ्यास करने वालों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दीं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने स्मरण दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव का रिकॉर्ड 177 देशों ने समर्थन किया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में इसके पश्चात स्थापित किए गए रिकॉर्डों का भी उल्लेख किया जैसे 2015 में कर्त्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने योग किया और पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयोजित योग कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों ने भाग लिया। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि आयुष मंत्रालय द्वारा गठित योग प्रमाणन बोर्ड ने भारत के 100 से अधिक संस्थानों और 10 प्रमुख विदेशी संस्थानों को मान्यता दी है।

योग दुनिया के हर कोने में दैनिक जीवन का हिस्सा

श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में योगाभ्यास करने वालों की संख्या बढ़ रही है और इसका आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि योग की उपयोगिता को लोग पहचान रहे हैं और शायद ही कोई ऐसा वैश्विक नेता हो जिसने अपने संवादों के दौरान योग पर चर्चा न की हो। उन्होंने कहा कि सभी वैश्विक नेता उनके साथ संवादों के दौरान योग में गहरी रुचि दिखाते हैं। श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा कि योग दुनिया के हर कोने में दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। दुनिया भर में योग की बढ़ती स्वीकार्यता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने 2015 में तुर्कमेनिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान एक योग केंद्र के उद्घाटन अवसर का भी स्मरण किया और कहा कि आज योग देश में बेहद लोकप्रिय हो गया है।

उन्होंने कहा कि तुर्कमेनिस्तान में राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालयों ने योग चिकित्सा को शामिल किया है, सऊदी अरब ने भी इसे अपनी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया है और मंगोलियन योग फाउंडेशन कई योग विद्यालयों का संचालन कर रहा है। यूरोप में योग की स्वीकार्यता के बारे में जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब तक 1.5 करोड़ जर्मन नागरिक योगाभ्यासी बन चुके हैं। उन्होंने इस वर्ष भारत द्वारा 101 वर्षीय फ्रांसीसी योग शिक्षिका के योग किए गए महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के अवसर को भी स्मरण किया, जबकि वह एक बार भी भारत नहीं आई थीं। श्री मोदी ने कहा कि योग आज शोध का विषय बन गया है और इस पर कई शोध पत्र पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं।

इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के विषय 'स्वयं और समाज के लिए योग' के बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया योग को वैश्विक कल्याण के एक शक्तिशाली संवाहक के रूप में देख रही है और यह हमें अतीत के बोझ से मुक्त करते हुए वर्तमान में जीने में सक्षम बनाता है। श्री मोदी ने कहा कि योग हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा कल्याण हमारे आस-पास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा है। जब हम भीतर से शांत होते हैं, तो हम दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि योग से प्राप्त प्रेरणा हमारे प्रयासों को सकारात्मक ऊर्जा देगी। श्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर, खासकर श्रीनगर के लोगों के योग के प्रति उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्रशासित प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने लोगों की इस भावना की भी प्रशंसा की कि वे बारिश के मौसम के बावजूद बाहर निकलकर अपना समर्थन दिखा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में योग कार्यक्रम के साथ 50,000 से 60,000 लोगों का जुड़ना बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनके समर्थन और भागीदारी के लिए धन्यवाद देकर किया और दुनिया भर के सभी योग उत्साही लोगों को अपनी शुभकामनाएं भी दीं। ■

चर्चा का मुख्य जोर आर्थिक सहभागिता पर रहा

22वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 जुलाई, 2024 को 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए। उनके आगमन पर हवाई अड्डे पर उनका औपचारिक स्वागत 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर किया गया। प्रधानमंत्री का स्वागत उप-प्रधानमंत्री श्री मंटुरोव ने किया। रूसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में एक विशेष निजी रात्रिभोज का आयोजन भी किया। 9 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय समुदाय से बातचीत की। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रोसाटॉम प्रदर्शनी स्थल का दौरा किया, जहां उनके साथ राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन भी उपस्थित रहे।

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने क्रेमलिन में अपनी विस्तृत चर्चा जारी रखी। दोनों नेताओं के बीच इस विस्तृत, व्यापक, बहुआयामी चर्चा का पहला दौर निजी रात्रिभोज के दौरान हुआ था, वहीं 9 जुलाई की चर्चा में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग एवं क्षेत्रीय विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच चर्चा का एजेंडा मुख्य रूप से आर्थिक रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन ने अपनी चर्चा में आर्थिक मुद्दों के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को कवर करने वाले आर्थिक विषयों पर बात की। रक्षा एवं सुरक्षा भी चर्चा का एक महत्त्वपूर्ण बिंदु रहा।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों एवं ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय समूहों की स्थिति की भी समीक्षा की। इस चर्चा का मुख्य जोर आर्थिक संबंधों पर रहा। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, विज्ञान-तकनीक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में नौ समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ■

प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' से सम्मानित किया गया

भारत-रूस संबंधों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी। रूसी राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान रूस के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित किया। ■

ऑस्ट्रिया और भारत ने कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया

ऑस्ट्रिया के चांसलर श्री कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9-10 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर गये। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति श्री अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात की और चांसलर श्री नेहमर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। यह प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी और 41 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। यह वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 75वां वर्ष है। भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के साझा मूल्य के साथ एक कानून-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर को केंद्र में रखा जाए। उन्होंने अधिक स्थिर, समृद्ध और सस्टेनेबल दुनिया के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गहरा एवं व्यापक बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चांसलर श्री नेहमर और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने माना कि दोनों देश अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वे इस साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए। इस उद्देश्य के लिए राजनीतिक स्तर की बातचीत के अलावा, उन्होंने भविष्योन्मुखी द्विपक्षीय सतत् आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी पर जोर दिया, जिसमें हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, जीवन विज्ञान, स्मार्ट शहर, परिवहन के साथ-साथ नवीन पहलों एवं संयुक्त परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान एवं नवाचार तथा व्यवसाय-से-व्यवसाय जुड़ाव पर काम करने की बात की। ■

प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया

इटली की प्रधानमंत्री सुश्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 50वें जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के अपुलिया गए। यह शिखर सम्मेलन 14 जून, 2024 को इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया था। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। जी-7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 11वीं भागीदारी थी और प्रधानमंत्री श्री मोदी लगातार पांचवीं बार जी-7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनें। 14 जून, 2024 को प्रधानमंत्री ने आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित अन्य देशों के साथ आउटरीच सत्र में भाग लिया। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इटली के अपुलिया में जी-7 शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में फिर से चुने जाने के बाद शिखर सम्मेलन में भाग लेना उनके लिए बहुत संतोष की बात है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के लिए इसे मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के एआई मिशन 'सभी के लिए एआई' पर आधारित बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य सभी की प्रगति और कल्याण को बढ़ावा देना होना चाहिए। इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने जापान, यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस सहित जी-7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चाएं हुईं। ■

18वीं लोकसभा का पहला और राज्यसभा का 264वां सत्र समाप्त

539 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ

दोनों सदनों में 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादकता रही

18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के बाद लोकसभा का पहला सत्र और राज्यसभा का 264वां सत्र क्रमशः 24 और 27 जून से बुलाया गया था। लोकसभा को 2 जुलाई, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि राज्यसभा को 3 जुलाई, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया

तीन जुलाई को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने संसद के इस सत्र की कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया। लोकसभा में पहले दो दिन 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ/प्रतिज्ञान के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। सत्र के दौरान कुल 542 सदस्यों में से 539 ने शपथ/प्रतिज्ञान लिया।

शपथ/प्रतिज्ञान की सुविधा के लिए भारत की राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत श्री भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया तथा श्री सुरेश कोडिकुन्निल, श्री राधा मोहन सिंह, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री टी.आर. बालू और श्री सुदीप बंद्योपाध्याय को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया, जिनके समक्ष सदस्य संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत शपथ/प्रतिज्ञान ले सकते हैं और उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

26 जून, 2024 को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और लोकसभा के सदस्य श्री ओम बिरला को ध्वनि मत से अध्यक्ष चुना गया। इसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय कराया।

27 जून, 2024 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें सरकार की पिछली उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया और साथ ही राष्ट्र के भविष्य के विकास के लिए रोडमैप का भी विवरण दिया गया।

27 जून, 2024 को प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद का राज्यसभा में परिचय कराया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 28 जून, 2024 को दोनों सदनों में शुरू होनी थी।

लोकसभा में व्यवधानों के कारण इस विषय पर बहस 1 जुलाई, 2024 को ही शुरू हो सकी। श्री अनुराग ठाकुर, सांसद ने बहस की शुरुआत की, जबकि सुश्री बांसुरी स्वराज, सांसद ने लोकसभा में चर्चा का समर्थन किया। कुल 68 सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया, जबकि 50 से अधिक सदस्यों ने अपने भाषण सदन के पटल पर रखे। 2 जुलाई, 2024 को 18 घंटे से अधिक चली चर्चा के बाद प्रधानमंत्री द्वारा बहस का उत्तर दिया गया। लोकसभा में लगभग 34 घंटे की अवधि में 7 बैठकें हुईं और एक दिन के व्यवधान के बावजूद उत्पादकता 105 प्रतिशत रही।

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 28 जून, 2024 को श्री सुधांशु त्रिवेदी, सांसद द्वारा शुरू की गई, जिसका समर्थन सुश्री कविता पाटीदार, सांसद द्वारा किया गया। कुल 76 सदस्यों ने 21 घंटे से अधिक चली बहस में भाग लिया, जिसका उत्तर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 जुलाई, 2024 को दिया गया। राज्यसभा की कुल उत्पादकता 100 प्रतिशत से अधिक रही।

मैंने भी एक पेड़ अपनी 'मां' के नाम लगाया है: नरेन्द्र मोदी

धरती 'मां' ही हम सबके जीवन का आधार है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती 'मां' का भी ख्याल रखें

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जून को 'आकाशवाणी' के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 111वीं कड़ी के प्रारंभ में हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में देशवासियों की सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं।

एक पेड़ 'मां' के नाम

'मन की बात' के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम सबके जीवन में 'मां' का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां, हर दुःख सहकर भी अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है। हर मां, अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था, हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान का नाम है – 'एक पेड़ मां के नाम'। मैंने भी एक पेड़ अपनी 'मां' के नाम लगाया है।

उन्होंने कहा कि मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को Social Media पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है— चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को #Plant4Mother और #एक_पेड़_मां_के_नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का एक और लाभ होगा। धरती भी 'मां' के समान हमारा ख्याल रखती है। धरती मां ही हम सबके जीवन का आधार है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती मां का भी ख्याल रखें। 'मां' के नाम पेड़ लगाने के अभियान से अपनी मां का सम्मान तो होगा ही होगा, धरती मां की भी रक्षा होगी। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देशभर में 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही मां के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गति देनी है।

हम संस्कृत को सम्मान दें, उसे दैनिक जीवन में स्थान दें

श्री मोदी ने कहा, "मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहं किञ्चित् चर्चा संस्कृत भाषायां आरभे। आप सोच रहे होंगे कि 'मन की बात' में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं? इसकी वजह है आज संस्कृत से जुड़ा एक

खास अवसर! आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। मैं आल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। आजकल ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरू में कई और लोग कर रहे हैं। बेंगलुरू में एक पार्क है— कब्बन पार्क! इस पार्क में यहां के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। यहां हफ्ते में एक दिन, हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहां वाद-विवाद के कई सत्र भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है— संस्कृत weekend! इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरूवासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोकप्रिय हो गया है। अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़ें तो हमें विश्व की इतनी प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

श्री मोदी ने कहा कि आज 30 जून का ये दिन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई-बहन 'हूल दिवस' के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो-कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। वीर सिद्धो-कान्हू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी-जान से मुकाबला किया और जानते हैं ये कब हुआ था? ये हुआ था 1855 में यानी ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी दो साल पहले हुआ था, तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई-बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। हमारे संथाली भाई-बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कान्हू शहीद हो गए। झारखंड की भूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है।

'मन की बात' के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब से एक सप्ताह बाद पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मेरी कामना है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सभी देशवासियों पर सदैव बनी रहे। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में पंढरपुर वारी भी शुरू होने वाली है। मैं इन यात्राओं में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। आगे कच्छी नववर्ष – आषाढी बीज का त्योहार भी है। इन सभी पर्व-त्योहारों के लिए भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1).................................. (2)..............................

ईमेल : ....

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.................................... दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में 21 जून, 2024 को आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मास्को (रूस) में 08 जुलाई, 2024 को रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ एक निजी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वियना (ऑस्ट्रिया) में 10 जुलाई, 2024 को ऑस्ट्रिया के चांसलर श्री कार्ल नेहमर के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अपुलिया (इटली) में 14 जून, 2024 को 50वें जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के दौरान एक समूह चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में 22 जून, 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के साथ मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
44 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 24 जुलाई, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह